

संघ ने देश के सामने आने वाली हर चुनौतियों का डटकर सामना किया : मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपनी प्राथमिकताओं को राष्ट्र की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करते हुए हर युग में देश के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना किया है।

श्री मोदी ने बुधवार को यहां आरएसएस के शताब्दी समारोह में कहा कि गुरुवार को विजयादशमी का महाव्रत है जो भारतीय संस्कृति के शाश्वत उद्घोष का प्रतीक है। ऐसे ही पावन अवसर पर शताब्दी वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कोई संयोग नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हजारों वर्षों से चली आ रही एक प्राचीन परंपरा का पुनरुद्धार है जिसमें राष्ट्रीय चेतना प्रत्येक युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए रूपों में प्रकट होती है। उन्होंने इस उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है।

100 रुपये के इस सिक्के पर एक ओर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न और दूसरी ओर स्वयंसेवकों द्वारा सलामी दिए जा रहे सिंघ के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित है। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में संभवतः यह पहली बार है जब भारत



माता की छवि भारतीय मुद्रा पर दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि 1963 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने देशभक्ति की धुनों पर ताल से ताल मिलाते हुए बड़े गर्व के साथ परेड में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि यह डाक टिकट उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति को समेटे हुए है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार महान नदियाँ अपने तटों पर मानव सभ्यताओं का पोषण करती है उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी

असंख्य जीवन को पोषित और समृद्ध किया है। एक नदी जो अपने माध्यम से बहने वाली भूमि, गाँवों और क्षेत्रों को आशीर्वाद देती है इसी प्रकार संघ ने भारतीय समाज के हर क्षेत्र और राष्ट्र के हर क्षेत्र को छुआ है। श्री मोदी ने कहा कि संघ के अनेक धाराओं में विस्तार के बावजूद उनमें कभी विभाजन नहीं हुआ।

श्री मोदी ने कहा, "अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक महान उद्देश्य - राष्ट्र निर्माण - को अपनाया है।" उन्होंने कहा कि संघ अपनी स्थापना के समय से ही देशभक्ति

और सेवा का पर्याय रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि विभाजन के कष्टदायक दौर में जब लाखों परिवार विस्थापित हुए थे, स्वयंसेवक सीमित संसाधनों के बावजूद शरणार्थियों की सेवा में सबसे आगे खड़े रहे। उन्होंने कहा कि यही समरसता और समवेशी समाज के संकल्प का आधार है, जिसे संघ नए जोश के साथ मजबूत करता रहता है।

राहत पहुंचाने वालों में से हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने संघ के साहस और सेवा भावना को प्रत्यक्ष रूप से देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जाति-आधारित भेदभाव जैसी गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक बुराइयाँ लंबे समय से हिंदू समाज के लिए एक गंभीर चुनौती रही हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. हेडगेवार से लेकर आज तक संघ के प्रत्येक सरसंघचालक ने भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत ने समाज के सामने सामाजिक समरसता का एक स्पष्ट लक्ष्य रखा है जिसमें "एक कुआँ, एक मंदिर और एक श्मशान" की बात कही गयी है। उन्होंने कहा कि संघ ने इस संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया है और भेदभाव, विभाजन और कलह से मुक्त समाज का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि यही समरसता और समवेशी समाज के संकल्प का आधार है, जिसे संघ नए जोश के साथ मजबूत करता रहता है।

श्री मोदी ने कहा कि एक सदी पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, उस समय की जरूरतें और संघर्ष अलग थे। भारत सदियों पुरानी

राजनीतिक पराधीनता से मुक्ति पाने और अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयासरत था। उन्होंने कहा कि आज जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है तो चुनौतियाँ भी बदल गई हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी से उबर रहा है, नए क्षेत्र युवाओं के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं और भारत कूटनीति से लेकर जलवायु नीतियों तक वैश्विक स्तर पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज की चुनौतियों में दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की साजिशें और जनसांख्यिकीय बदलाव शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सरकार इन मुद्दों का शीघ्रता से समाधान कर रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भरता अब एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। प्रधानमंत्री ने समाज से स्वदेशी के मंत्र को सामूहिक संकल्प के रूप में अपनाने का आह्वान किया और सभी से "वोकल फॉर लोकल" अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा समर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पांच

परिवर्तनकारी संकल्प - आत्म-जागरूकता, सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक प्रबंधन, नागरिक अनुशासन और पर्यावरण चेतना - महत्वपूर्ण साधन हैं जो राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाएंगे, भारत को विविध चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए आधारभूत स्तंभ के रूप में काम करेंगे।

" इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री शेखावत ने कहा कि संघ केवल एक संगठन नहीं राष्ट्र निर्माण की प्रखर पाइपलाइन है। इसने देश को नई ऊर्जा देने का काम किया। संघ लगातार सौ वर्षों से काम करता रहा आज यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। दृढ़ भावना के साथ समाज में एकता बनाने के रूप में इसकी पहचान बनी। श्री होसबोले ने नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता है। कल संघ के विजय यात्रा में एक विशेष विजय दशमी है। संघ ने सौ विजयादशमी देखी है।

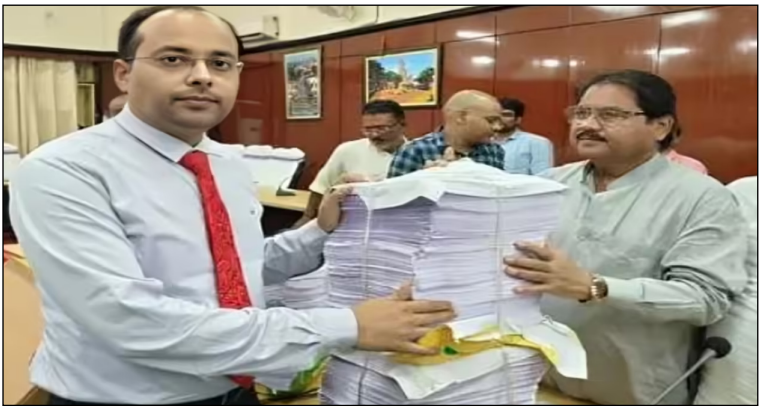
बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी

7.42 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। अंतिम मतदाता सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग इस कार्य को सफल बनाने के लिए बिहार के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित हुई, जिसमें लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं।

ईसीआई के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रतियां राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही हैं। कोई भी मतदाता इसे वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट गव डॉट इन पर ऑनलाइन देख सकता है। यह एसआईआर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बिहार, सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), 243 निर्वाचन निबंधन अधिकारियों (ईआरओ), 2,976 सहायक निर्वाचन निबंधन अधिकारियों (ईईआरओएस), लगभग 1 लाख बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), लाखों स्वयंसेवकों और सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी, जिसमें उनके जिला अध्यक्ष और उनके द्वारा नियुक्त 1.6 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट (बीएएल) शामिल हैं, के



ईमानदार प्रयासों से सफल हुआ।

आयोग नियमित रूप से जागरूकता फैलाने और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को भी धन्यवाद देता है। एसआईआर प्रक्रिया को समझाने और उन्हें पूरी जानकारी रखने के लिए राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। 20 जुलाई तक सीईओ, डीईओएस, ईआरओएस और बीएलओ ने पात्र मतदाताओं की पहचान करने के उद्देश्य से, मृत घोषित किए गए, जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, जो स्थायी रूप से पलायन कर गए, या जिनका पता नहीं लगाया जा सका, ऐसे मतदाताओं की बूथ-स्तरीय सूचियां राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी थीं।

ड्राफ्ट मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। साथ ही, ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए

नामों की सूची डीईओ या डीएम (जिलावार) के साथ-साथ सीईओ बिहार की वेबसाइट पर भी जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई थी। एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और भारत के निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य 'कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो' के अनुरूप की गई थी। अगर कोई पात्र व्यक्ति अभी भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक आवेदन जमा कर सकता है।

अगर कोई व्यक्ति फाइनल वोटर लिस्ट में प्रविष्टि के संबंध में ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील और

बिहार के मतदाताओं, अधिकारियों, दलों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया धन्यवाद

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर राज्य के सभी मतदाताओं और एसआईआर के काम में लगे अधिकारियों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के अध्यक्षों को उनके काम और सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया है। आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार की सूची के एसआईआर के सम्पन्न होने पर राज्य के मतदाताओं, बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), सहायक ईआरओ (ईईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ), तथा राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त सभी बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलओ), सभी मान्यता प्राप्त दलों के जिला अध्यक्षों, राज्य अध्यक्षों और राष्ट्रीय अध्यक्षों को धन्यवाद दिया है। बिहार में 22 वर्षों के अंतराल के बाद एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। यह काम 24 जून को शुरू हुआ और मंगलवार को पक्की सूची जारी की गयी।

सीईओ के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

सीडीएस चौहान ने परमाणु हथियारों के जैविक खतरों से तैयार रहने का आह्वान किया

○ कोविड महामारी के बाद बढ़ते जैविक खतरों के प्रति हमें भविष्य में तैयार रहना चाहिए



नई दिल्ली, एजेंसी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को भविष्य के लिए परमाणु हथियारों से होने वाले जैविक खतरों के खिलाफ तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के डेटा केंद्रित युद्ध के युग में हमना तक पहुंच दुश्मन को या तो घुम पर बढ़त दिला सकती है या उसे कुछ हद तक बढ़त दिला सकती है। हालांकि, डेटा सुरक्षा और डेटा संरक्षण सीधे तौर पर परमाणुस की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको इन सभी प्रकार की चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए।

दिल्ली कैंट स्थित मोनेकशॉ सेंटर में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) के 100वें स्थापना दिवस पर वैज्ञानिक सत्र को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। हालांकि, हमारी ओर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना

बहुत कम है, फिर भी इसे हमारी सुरक्षा में शामिल करना समझदारी होगी। रेडियोलॉजिकल प्रदूषण के लिए अलग प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है और यह हमारे प्रशिक्षण का हिस्सा होना चाहिए। परमाणु खतरों के विरुद्ध तैयारी इसके उपयोग के विरुद्ध निवारक उपाय में योगदान करती है। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है।

उन्होंने सैन्य नर्सिंग सेवा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय डीएनए अद्वितीय है। हमारी प्रतिक्षा प्रणाली अलग-अलग वातावरण या संक्रमणों के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया करती है। व्यापक स्तर पर व्यक्तिगत चिकित्सा डेटा की सुरक्षा हमें उसनी ही महत्वपूर्ण है और इसमें केस हिस्ट्री, रिपोर्ट और चिकित्सा स्वास्थ्य रिकॉर्ड शामिल हैं। परिचालन डेटा, स्वास्थ्य पैटर्न से संबंधित तैनाती, निकासी योजनाओं को भी लौक से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। चिकित्सा डेटा की भूमिका-आधारित पहुंच और एंक्रिप्शन

आज के डेटा केंद्रित युद्ध के युग में बहुत प्रासंगिक है। सूचना तक पहुंच दुश्मन को या तो हम पर बढ़त दिला सकती है या उसे कुछ हद तक बढ़त दिला सकती है। हालांकि, डेटा सुरक्षा और डेटा संरक्षण सीधे तौर पर एमएनएस की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको इन सभी प्रकार की चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए।

सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि कोविड महामारी के बाद के युग में जैविक खतरों के बढ़ने की संभावना है और उन्होंने उनके खिलाफ रक्षा तैयारियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान दुनिया गहन यात्राओं और क्लेशों के दौर से गुजर रही है। भविष्य में मानव निर्मित, आकस्मिक या प्राकृतिक जैविक खतरों बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ऐसे खतरों से बचाव और संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के लिए अलग उपचार प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। हमें भविष्य में इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

यूजीसी का जानकारी साझा न करने वाले 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश के विभिन्न राज्यों के 54 अलग-अलग प्राइवेट विश्वविद्यालयों के लिए नोटिस जारी किया है। ये सभी वे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिन्होंने यूजीसी के तय मानकों का अनुपालन नहीं किया। इन विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के नियमानुसार 'सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर' जारी नहीं किया है।

यूजीसी के दिशानिर्देश कहते हैं कि इस नियम के तहत विश्वविद्यालयों को वेबसाइटों पर संस्थान से संबंधित आवश्यक जानकारी साझा करनी होती है। यह सार्वजनिक जानकारी सहज उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए छात्रों, अभिभावकों या किसी भी अन्य व्यक्ति को वेबसाइट पर



लॉगिन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन देशभर के 54 विश्वविद्यालयों ने यह जानकारी अब तक साझा नहीं की है।

यही कारण है कि अब यूजीसी ने इन निजी विश्वविद्यालयों को अपने-अपने संस्थानों की जानकारी देने का नोटिस दिया है। वहीं, अब इसके जवाब में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने अपने दस्तावेज

खंगालना शुरू कर दिए हैं। कुछ का कहना है कि वे अपने पोर्टल पर यह जानकारी साझा करने जा रहे हैं। हालांकि, अब पोर्टल के अलावा यूजीसी को भी यह जानकारी भेजनी होगी।

दरअसल, यूजीसी का कहना है कि उनके द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश विश्वविद्यालय संबंधी शिक्षण में पारदर्शिता को बढ़ाने देने के लिए हैं।

लड़ाकू विमानों के लिए एचएएल को मिला चौथा जीई-404 जेट इंजन

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय फाइटर जेट एलसीए एमके-1ए के निर्माण में तेजी आ रही है। इस श्रेणी के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस एलसीए एमके-1ए के लिए भारत के एचएएल को चौथा जीई-404 जेट इंजन मिल गया है। यह जानकारी बुधवार को दी गई। एचएएल को बीते महीने सितंबर में हो तीसरा जेट इंजन मिला था।

एचएएल को इस वित्त वर्ष के अंत तक कुल 12 जीई-404 जेट इंजन मिलने की संभावना है। ये सभी इंजन भारतीय लड़ाकू विमान तेजस मार्क-1ए में लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि अमेरिकी कंपनी भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह जेट इंजन सप्लाई कर रही है। एचएएल के अधिकारियों ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि, उन्हें एलसीए एमके-1ए के लिए चौथा जीई-



404 इंजन मिला है।

एचएएल का कहना है कि इंजन आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होने से लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए से उत्पादन और वायुसेना को इसकी डिलीवरी देने के कार्यक्रम में गति आएगी।

दरअसल भारतीय वायुसेना ने तेजस एमके-1ए विमानों के निर्माण का ऑर्डर दिया है, जिन्हें आने वाले वर्षों में क्रमिक रूप से

डिलीवर किया जाएगा। यह विमान आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर हथियार क्षमता और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस होंगे। भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए हाल ही में एक नया अनुबंध किया गया है। इस करार के मुताबिक 62 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भारतीय वायुसेना को 97 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट

उपलब्ध कराए जाएंगे।

इन लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 97 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस एमके-1ए की खरीद हेतु 62,370 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। अनुबंध के मुताबिक इनमें 68 सिंगल-सीटर लड़ाकू विमान और 29 टिवन-सीटर ट्रेनर विमान शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस आपूर्ति से भारतीय वायुसेना की क्षमता को और मजबूती मिलेगी। लड़ाकू विमानों की डिलीवरी की समय-सीमा की बात करें तो इन विमानों की डिलीवरी वर्ष 2027-28 से शुरू होगी। तब अनुबंध के मुताबिक भारतीय वायुसेना को इन लड़ाकू विमानों की आपूर्ति अगले छह वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। ये विमान स्वदेशीकरण

पर आधारित होंगे और इनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकी विशेषताएं होंगी।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस परियोजना में 64 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा। जनवरी 2021 में हुए पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमके-1ए अनुबंध की तुलना में इस बार 67 अतिरिक्त स्वदेशी उपकरण शामिल किए गए हैं।

इसमें कई प्रमुख उन्नत प्रणालियां सम्मिलित हैं। भारत के ये स्वदेशी लड़ाकू विमान ह्यउत्तम एड्रेंसएड्ड रडार से लैस होंगे। यह सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। इसमें ह्यस्वर रक्षा कवचह्छ प्रणाली व स्वदेशी नियंत्रण सतह एक्ट्यूएटर्स होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक इन उन्नत तकनीकों से विमान की युद्धक क्षमता और आत्मनिर्भर भारत पहल को और बल मिलेगा।

अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, मरीज हो रहे परेशान

प्रभेश मिश्रा

छत्तीसगढ़: जिला सूरजपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार है स्थिति यह है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी व सिविल सर्जन जिला अस्पताल व्यवस्थित ढंग से चला पाने में नाकामयाब डॉक्टर समय पर आते नहीं पर समय से पहले चले जरूर जाते हैं। ऐसी व्यवस्था आखिर छत्तीसगढ़ के जिला अस्पतालों में कैसे बन गई है। डॉक्टर आते भी हैं तो मरीजों को बस अपने क्लीनिक तक पहुंचने के लिए। उसके बाद फिर वह चले जाते हैं। यह आरोप अब मरीजों का जिला अस्पताल से सामने आने लगा है।

लगातार सूरजपुर जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उंगली उठने लगी है यहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व सिविल सर्जन से व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है उनकी बात शायद डॉक्टर मन नहीं रहे हैं या तो इनका डर डॉक्टरों में अब है ही नहीं इस वजह से डॉक्टर भी अपनी मनमानी पर उतावला है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि स्वास्थ्य



मंत्रों के संभाग वाले जिले अस्पताल की ऐसी स्थिति है, तो फिर बाकी अस्पतालों की स्थिति क्या होगी यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूरजपुर व सिविल सर्जन सूरजपुर से व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री इन्हें हटा क्यों नहीं देते। ऐसे अधिकारी क्यों नहीं रखते हैं, जो बेहतर ढंग से सेवा दे पाएं और कर्मचारी व डॉक्टर भी समय पर अस्पताल आए और मरीज को

इंतजार बिना कारण उनका इलाज करें। जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सकों की मनमानी से मरीजों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीज समय पर डॉक्टरों को नहीं पाते। परिणामस्वरूप कई बार उन्हें घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है, तो कई मजबूर होकर बिना इलाज कराए ही लौट जाते हैं। नियम के मुताबिक सुबह 9 बजे से

चिकित्सकों की ड्यूटी प्रारंभ होनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश डॉक्टर 10 बजे के बाद ही अस्पताल पहुंचते हैं। इससे सुबह जल्दी आने वाले मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। मरीजों का कहना है कि समय पर पहुंचने में देरी करने के बाद भी डॉक्टर अपने चैबर में लगातार नहीं बैठते। वे इधर-उधर समय बिताते नजर आते हैं। कई बार गंभीर मरीज भी डॉक्टर को दौड़ते

रह जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। डॉक्टरों की लापरवाही यहीं तक सीमित नहीं है। जानकारी के अनुसार कई चिकित्सक दोपहर 1 बजे से पहले ही अस्पताल छोड़ देते हैं। जिससे बाद में आने वाले मरीजों को न तो परामर्श मिलता है और न ही उचित इलाज। शाम की पाली में तो हालत और भी है खराब शाम की पाली में तो स्थिति और भी चिंताजनक है।

अधिकांश चिकित्सक शाम को ड्यूटी पर पहुंचते ही नहीं। परिणामस्वरूप अस्पताल की दूसरी पारी लगभग नाम मात्र की रह जाती है। ऐसे में जो मरीज शाम को इलाज के लिए आते हैं, उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। मरीजों की बढ़ती परेशानी। इस लापरवाही का सीधा असर आम मरीजों पर पड़ रहा है।

दूर-दराज से आने वाले ग्रामीण मरीजों को सबसे अधिक परेशानी होती है। उन्हें इलाज कराने के लिए पूरे दिन का समय और अतिरिक्त खर्च दोनों झेलना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों की मनमानी पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। वे मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस, नियमित निरीक्षण और कठोर कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। लोगों को उम्मीद है कि वर्तमान कलेक्टर इस स्थिति पर ध्यान देंगे और जिला अस्पताल की अव्यवस्था को सुधारेंगे।

महात्मा गांधी की जयंती पर मानक मऊ मंडल में स्वच्छता अभियान चलाया



राकेश कुमार शर्मा

उत्तर प्रदेश: आज सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भूत पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के उपलक्ष में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष में मानक मऊ मंडल 100 फुटा रोड गलीरा अंबेडकर पार्क व आसपास में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिसमें मुख्य रूप से मंडल के

प्रभारी आदरणीय हेमंत अरोड़ा जी वार्ड नंबर 2 से पार्श्व सुनील पवार जी वार्ड नंबर 4 से अनिल गर्ग जी वार्ड नंबर 25 से सोपिन कुमार पाल जी वार्ड नंबर 9 से मोहर सिंह जी मंडल के महामंत्री अनिल मंडल उपाध्यक्ष मुरारी खेतवाल जी अनिल सेन जी शक्ति केंद्र संयोजक राकेश शर्मा जी मंडल मंत्री विजेंद्र शर्मा जी मंडल महामंत्री जयवीर खटाना जी पूर्व पार्श्व राजेंद्र जी पंजोरा गांव के अध्यक्ष विपिन सिंह वह मंडल के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विजयदशमी पर दशहरा मैदान किशनगढ़ बास में केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बने मुख्य अतिथि

जयवीर सिंह

राजस्थान: विजयदशमी के पावन अवसर पर स्थानीय दशहरा मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव तथा किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल के नेतृत्व में अतिथियों का पुष्पमालाओं व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रीराम जी की रामायण एवं हनुमान जी की आरती कर रामलीला का शुभारंभ किया। रामलीला कमेटी द्वारा केन्द्रीय मंत्री



एवं पूर्व विधायक को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंच से संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विजयदशमी के इस पावन पर्व पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक

शुभकामनाएं देता हूँ। आज महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है, हमें उनके आदर्शों को जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने नवरात्रों में जीएसटी में राहत दी है,

जिससे आमजन को सीधा लाभ मिला है। साथ ही उन्होंने अपील करी 'हर दुकानदार अपनी दुकान पर 'स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो' का बोर्ड लगाएं, ताकि भारत में निर्मित वस्तुओं का अधिक उपयोग हो और देश की अर्थव्यवस्था सशक्त बने। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महा सिंह चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष तारामणि सतीश सिसल, मंडल उपाध्यक्ष व पार्श्व तेज सिंह सैनी, जिला महामंत्री अनुप यादव सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं नगर पालिका पार्श्वदण मोजुद रहे। इस अवसर पर कला मंच समिति द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया।

जोबट विधायक सेना पटेल ने कैबिनेट मंत्री समेत चार पर किया केस

साबिर मोहम्मद मंसूरी

मध्य प्रदेश: जोबट की विधायक सेना पटेल ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ आलोराजपुर कोतवाली में गंभीर शिकायत दर्ज** कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 26 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से उनके खिलाफ असत्य और अपमानजनक संदेश फैलाए गए।

सोशल मीडिया संदेशों में जोबट विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक पटेल को दारू माफिया का संरक्षक आपराधिक परिवार का सहयोगी बताया गया और उन्हें हत्या, बलात्कार व अपहरण जैसे संगीन अपराधों से जोड़ने की



कोशिश की गई। विधायक ने इस कृत्य को उनके व्यक्तिगत सम्मान और महिला जनप्रतिनिधि की गरिमा पर हमला करार देते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सीधा प्रहार बताया। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की राजनीति अस्वीकार्य है। इसी बीच आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने भी आरोपियों की हरकत की कड़ी निंदा की है।

कोटकासिम में भाजपा ने गांधी-शास्त्री जयंती श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाई

जयवीर सिंह

राजस्थान: भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कोटकासिम पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके जीवन मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गांधी जी के ह्स्वदेशी आंदोलन के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता संग्राम के समय थे। वहीं शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करते हुए सभी ने देश की उन्नति के लिए किसान और सैनिकों के सम्मान पर बल दिया। गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला, आध्यात्मिक गुरु एवं संस्थापक पवित्र



मनन दीप सत्संग सेवा संस्थान कोटकासिम। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष यशपाल शर्मा, आध्यात्मिक गुरु एवं संस्थापक पवित्र मनन दीप सत्संग सेवा संस्थान कोटकासिम भास्कर भारद्वाज, मुनेश यादव, एमपीएस कप्तान चौधरी,

प्रेम गुप्ता, धनाराम, माडु राम, जितेंद्र खेरा, विनोद कुमार, पवन कुमार, देवकीनंदन शर्मा, लीलू राम, जंगी प्रजापत, नगरपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश सैनी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कालावाली के महाराजा अग्रसेन पार्क में दशहरा पर्व को लेकर हुआ रावण दहन कार्यक्रम

महिपाल सिंह

हरियाणा: कालावाली के महाराजा अग्रसेन पार्क में वीरवार को दशहरा पर्व को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समाजसेवी संस्था इनरव्हील क्लब व महाराजा अग्रसेन कीर्तन मंडली कालावाली की ओर से करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान आरती, रावण दहन, डांडिया, गरबा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम के दौरान माता रानी का सजा भव्य पंडाल और महिलाओं के द्वारा लगाई गई स्वदेशी सामान की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। बच्चों व महिलाओं ने डांडिया व गरबा करके और कई मनोरंजन खेल खेलकर खूब मनोरंजन किया। इनरव्हील क्लब की प्रधान सुरेंद्र मक्कड़ व उप-प्रधान डॉ मीनाक्षी ने बताया कि दशहरा



केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत का सजीव उदाहरण है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को रामलीला से जुड़े प्रसंगों को समझाने का आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वे पाप और पुण्य के फर्क को समझ सकें। इस मौके पर इनरव्हील क्लब की प्रधान सुरेंद्र मक्कड़,

उप-प्रधान डॉ मीनाक्षी, सचिव कीर्ति गर्ग, फाउंडर प्रेसिडेंट गुलशन अरोड़ा, कोषाध्यक्ष रेखा गोयल, एडिटर ऊषा गर्ग, मनीष, सोरभ, चिराग, लवली, राम, गोल्डी, कर्मबीर सहित कई सदस्य मौजूद रहे। फोटो- कालावाली। कार्यक्रम के दौरान डांडिया व गरबा करती महिलाएं।

वाव-थराद में विजयादशमी पर जनसमागम, नेताओं का सम्मान और अंबाजी में शस्त्र पूजन

चौधरी राजुभाई वेणाभाई

गुजरात: सुईगाम तालुका भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मणभाई पटेल, उमेदान गढ़वी, नरसिंहभाई भाटा, रमेशभाई जाखेसरा, विक्रमसिंह जडेजा और अन्य नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी और बनासकांठा प्रभारी मंत्री बलवंतसिंह राजपूत को धरणीधर की तस्वीर देकर और पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में वाव विधायक स्वरूपजी ठाकौर समेत कई नेता मौजूद थे।

बनासकांठा जिले से अलग हुए वाव-थराद में आज दशहरे के दिन सुईगाम, वाव, भाभर और अन्य तालुकाओं से बड़ी संख्या में लोग जिले के विभिन्न कार्यालयों को चालू करने के लिए एकत्रित हुए। विजयादशमी के शुभ अवसर पर अंबाजी पुलिस ने शस्त्र पूजा की असत्य पर सत्य की विजय के



पर्व विजयादशमी से अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। इस दिन माताजी का नवल नोरता संपन्न होने के बाद, शमी वृक्ष की पूजा के अलावा, शुभ मुहूर्त में शस्त्र पूजन भी किया जाता है। अंबाजी में, विजयादशमी के पावन पर्व को मनाने के लिए दोपहर में गाँव में शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें राम परिवार के दर्शन कराए गए। इसके

अलावा, शाम को मानसरोवर स्थित शमी वृक्ष का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया गया। पुलिस व्यवस्था के महत्वपूर्ण शस्त्र, जो जनता की रक्षा का कार्य करते हैं, का भी शुभ मुहूर्त में विद्वान पंडित द्वारा पूजन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक सहित अंबाजी पुलिस थाने का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

एक नजर

जनसेवा और आस्था के माध्यम से जनता का विश्वास से जीत रहे डीजीएस परिवार

इंद्रेश कुमार पांडे/उत्तर प्रदेश: मेजा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता इन्द्रदेव शुक्ल "राजू भइया" और उनका परिवार लगातार सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की सेवा में जुटा हुआ है। जनसेवा को सर्वोच्च धर्म मानते हुए उनके परिवार ने कई पहलें शुरू की हैं। हर वर्ष सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन कर 51 कन्याओं का विवाह कराया जाता है। इसके अलावा 51,000 वृक्षारोपण संकल्प यात्रा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। गरीब और जरूरतमंदों के लिए 25,000 कंबल वितरण, नेत्र शिविर तथा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी चलाई जा रही है। वहीं राष्ट्रवादी संगोष्ठी और जय माँ शीतला कृपा महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के जरिए आस्था, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति से लोगों को जोड़ा जा रहा है। परिवार के सूरज देव शुक्ल, ब्रह्म देव शुक्ल, ईश्वर देव शुक्ल और इन्द्रदेव शुक्ल (राजू भइया) ने अपने जीवन को जनहित और राष्ट्र सेवा को समर्पित बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीजीएस परिवार का वही समर्पण मेजा क्षेत्र में जन-जन का विश्वास जीतने का सबसे बड़ा कारण है।



इंदौर के गौहर नगर में दशहरे पर देश के पहले रावण मंदिर में रावण की विधिवत पूजा हुई



नीतिन लाहौर/मध्य प्रदेश: इंदौर में दशहरे के अवसर पर एक अनोखी परंपरा का पालन किया गया, जहां रावण की पूजा की गई। अर्जुन सिंह गौहर नगर परदेशीपुरा रोड नंबर 2 पर स्थित प्रखंड पंडित विद्वान रावण के मंदिर में महेश गौहर, राजेंद्र घोंसरे और सूरज गुहार ने विधि-विधान से रावण की पूजा की। महेश गौहर ने बताया कि यह देश का पहला रावण मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष दशहरे पर रावण की पूजा की जाती है। सुबह पंचांग रस के साथ दूध, दही और फलों के रस से रावण का स्नान कराया गया। इसके बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना और हवन किया गया पूजा के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महेश गौहर ने बताया कि रावण एक महान विद्वान और तार्किक थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। रावण की बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता की प्रशंसा करते हुए महेश गौहर ने कहा कि वे एक अद्वितीय व्यक्ति थे इस अवसर पर पूजा में शामिल हुई। श्रीमती सीमा नरवाले पूजा में शामिल हुई। श्रीमती सविता धीलपूर पूजा में शामिल हुई। रमेश कल्याणी पूजा में शामिल हुए।

राजपुर रोड पर हर्षोल्लास के साथ रावण दहन, बाजार में गुंजे जय श्री राम के जयकारे



सूर्य देव/उत्तर प्रदेश: विगत वर्षों की भांति गत वर्ष भी परंपरागत तरी.से रावण के पुतले का दहन हर्षोल्लास के साथ किया गया। राजपुर रोड पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से रथ पर सवार होकर निकले। शान्की स्वरूप भगवान श्री रामजी साथ में लक्ष्मण व हनुमान जी की सेना व रावण की सेना के साथ पूरे बाजार का भ्रमण के उपरांत बाजार में स्थित जिला सहकारी गोदाम के पहुंचे, जहां पहले से प्रतिक्रामक रावण व राम युद्ध सजे कलाकारों के द्वारा दिखाया गया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से पूरा बाजार गुंजायमान हो उठा और देर शाम होते ही रावण के पुतले का दहन किया गया। शाम होते ही ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे और पूजा पंडालों में भी दर्शकों का हजूम उमड़ पड़ा। मेले में हजारों की संख्या में जगह-जगह खेल खिलौने, मिठाईयां भी खरिदारी करते हुए लोग नजर आए। मेले के दौरान स्थानीय बाजार के समस्त कमेटी के पदाधिकारी व थानाध्यक्ष राजेश सरोज व चौकी प्रभारी अजय श्रीवास्तव अपने दल बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे।

बहुचराजी जीआरडी जवान ने चोर को पकड़ा, बड़ी चोरी होने से टली



राजपूत रणजीत/गुजरात: बहादुर जीआरडी जवान ने चोर को पकड़कर चोरी की कोशिश नाकाम की बहुचराजी कस्बे में रात्रि गश्त के दौरान ग्राम रक्षक दल (जीआरडी) के एक सतर्क और बहादुर जवान की समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ी चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। जवान ने दुकानों के ताले तोड़ते हुए एक चोर को रथ हाथों पकड़ लिया, जिसकी पुलिस ने जमकर तारीफ की। घटना के विवरण के अनुसार, 29 और 30 सितंबर, 2025 की मध्य रात्रि लगभग 2 बजे, बहुचराजी पुलिस स्टेशन की जीआरडी इकाई में कार्यरत जवान बाबूभाई खेंगरभाई राठौड़ रात्रि गश्त पर थे। इसी दौरान उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को लोहे की रॉड से कस्बे की तीन-चार दुकानों के ताले तोड़ते देखा। बिना समय गँवाए, बाबूभाई ने बहादुरी से चोर को चुनौती दी और उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

पीओके में ‘जय हिंद’

पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आजकल नारे लगाए जा रहे हैं-‘जय हिंद, जय हिंद। वहां के लोग पाकिस्तान की हुकूमत और फौज से इतने आजिज आ चुके हैं कि वे अब भारत में विलुप्त चाहते हैं। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पीओके में रोजी-रोटी, आम ज़िंदगी, रोजगार, महंगाई और संसाधनों की लूट के मद्देनजर आंदोलन चलाए जाते रहे हैं। हुकूमत को ज़ापन भी दिए गए हैं, लेकिन अब वहां की अवाम विद्रोह पर उतर आई है। ऐसे भी नारे लगाए जा रहे हैं-ह्रयह जो दहशतगदी है, उसके पीछे वर्दी है। विद्रोहियों ने फौज और पुलिस के वदीधर्मियों पर प्रतिघात भी किए हैं। बलूचिस्तान में फौज का अस्तित्व लंबे वक्त से बलूच लड़ाकों के रहम-ओ-कर्म पर है। हाल ही में क्वेटा में एक ताकतवर बम विस्फोट किया गया, जिसमें 10 मौतें हो गईं और कई घायल हुए। अब आसार पुख्ता होने लगे हैं कि पाकिस्तान का विभाजन अपरिहार्य है। पीओके और बलूच के अलावा खैबर और सिंध में भी आजादी के आंदोलन जारी हैं। पीओके के विद्रोही ‘आजाद’ होने पर आमादा हैं। बलूच अपनी ‘आजादी’ के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। वे अपने बेशकीमती खनिजों का सौदा, पाकिस्तानी हुकूमत के द्वारा, अमरीका या चीन के साथ, करने का धुर विरोध कर रहे हैं। बलूच इन प्राकृतिक संसाधनों को अपनी स्वाभाविक, अमूल्य संपदा मानते रहे हैं, लिहाजा सौदेबाज हुकूमत और फौज के चेहरों पर जानलेवा प्रहार भी करते रहे हैं। पीओके के संदर्भ में 1994 से कई बार हमारी संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी हिंदुस्तान का अविभाज्य हिस्सा है। पाकिस्तान उसे लौटा दे। यह मुद्दा प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भी उठाते रहे हैं। दरअसल भारत सैन्य कार्रवाई को ‘अंतिम विकल्प’ मानता है। पीओके स्वतंत्र भारत की सुबह में ही तत्कालीन सत्ताधीशों की ऐतिहासिक गलतियों की भी डगवनी याद को ताजा करता है।

यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू अचानक युद्धविराम का फैसला नहीं करते, तो पीओके अस्तित्व में ही नहीं आता। तत्ीजनत करीब 72,935 वर्ग किमी क्षेत्रफल का भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में ही रहा, जो आज भी यथावत है। बल्कि 42,735 वर्ग किमी का भूभाग आज भी चीन अधिकृत कश्मीर कहलाता है। उसमें अक्साई चिन आदि के क्षेत्र आते हैं। भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर 1,06,566 वर्ग किमी में है, जबकि इससे दोगुने क्षेत्र का विलय भारत में हुआ था। बहरहाल उस गलती के 78 लंबे साल गुजर चुके हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर समय-समय पर बयान देते रहे हैं कि पीओके के निवासी, अपने विद्रोह के बूते, अपने आप हमारी तरफ लौट आएंगे। यह भरोसा भावुक और कहानीमय तो हो सकता है, लेकिन हम इसे बिल्कुल भी आसान नहीं मानते, क्योंकि वहां के क्षेत्रों में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। चीन अरबों रुपए खर्च कर चुका है और अपने इंजीनियरों और कर्मचारियों को भी मरवा चुका है। चीन के मंसूबे विस्तारवादी भी हैं। लिहाजा पीओके को बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ें? पड़ेगी। बेशक पाकिस्तान के पास सशस्त्र सेना भी है। वह आज भी बम गिरा कर या गोलीबारी में अपने ही मुल्क के लोगों को मार रहा है। याद रहना चाहिए कि अक्तूबर, 1947 में पाकिस्तान के फौजियों ने, कबायलों के मुखौटे पहन कर, तत्कालीन कश्मीर रियासत पर हमला बोल दिया था। महाराजा हरिसिंह ने भारत सरकार से सुरक्षा की गुहार की थी, लिहाजा तय शर्तों के मुताबिक अक्तूबर, 1947 के अंत तक महाराजा ने विलय-पत्र पर दस्तखत कर दिए और जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। उस दौर में देश की 550 से ज्यादा रियासतों ने भी भारत में ही अपने विलय कर दिए थे। इस तरह भारत संघ की रचना हुई और देश में संप्रभुता, एकता, अखंडता का माहौल बना। अब पीओके भारत में विलय के लिए तैयार है, लेकिन वहां हिंदुओं की संख्या सात करोड़ 89 लाख थी, जो अब घट कर सात करोड़ 42 लाख हो गई है। इस आधार पर कह सकते हैं कि सिर्फ 47 लाख नाम घटे हैं। लेकिन असल में करीब 69 लाख नाम कटे हैं। यह सात करोड़ 42 लाख की जो संख्या दिख रही है उसमें साढ़े 21 लाख नाम ऐसे हैं, जो नए जोड़े गए हैं। सो, चुनाव आयोग ने अपनी ओर से एसआईआर का काम पूरा कर दिया है। अगले कुछ दिन में एक पूरक सूची आ सकती है, जिसमें कुछ और नए नाम होंगे। लेकिन सवाल है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने से सारे सवालों के जवाब मिल गए? इसको लेकर जितने संदेह थे, सब दूर हो गए? क्या अब सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा मामला बंद हो जाएगा या वहां नए सवाल खड़े होंगे?

ध्यान रहे एसआईआर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लौबत है। सर्वोच्च अदालत ने मतदाता के सत्यापन के एक दस्तावेज के तौर पर आधार को शामिल करने और जिन लोगों के नाम कटे थे उनके ऑनलाइन आवेदन लेने का जिस

1970 के दशक तक एक बड़ा वर्ग गांवों से बाहर बसने लगा, बेहतर सुविधाओं और जीवनशैली की तलाश में। जब पहाड़ों में न तो कृषि का विकास हुआ और न ही कोई औद्योगिक ढांचा खड़ा हो पाया, तब लोगों ने स्थायी रूप से तराई, मैदानों और राज्य से बाहर के शहरों में बसने की योजना बनाई। 1970 के दशक में अर्थशास्त्रियों ने उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ‘मनी ऑर्डर इकोनॉमी’ कहा। बाद में जब लोग बाहर ही बसने लगे और पेंशन पर निर्भर हो गए, तो मैंने इसे ‘पेंशन इकोनॉमी’ कहा। आज स्थिति यह है कि कई गाँव ‘भूतिया गाँव’ बन चुके हैं, जहाँ पेंशनभोगी भी लौटना नहीं चाहते।

जब प्राथमिक क्षेत्र टिकाऊ नहीं रहा और द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र कभी शुरू ही नहीं हो पाए, तो राज्य का विकास ठहर गया। 1970 के दशक में जो पलायन शुरू हुआ था, वह आज और भी बढ़ गया है। पुश और पुल फैक्टर लगातार लोगों को बाहर ले जा रहे हैं। आज आवश्यकता है चकबंदी यानी भूमि समेकन की, जिससे समग्र विकास कार्यों की शुरूआत हो सके। आज की स्थिति यह है कि पुलिस कारस्टेबल या चपरासी की नौकरियों के लिए भी आवेदन करने वालों में डिग्रीधारी, इंजीनियर, एमबीए और पीएचडी धारक तक शामिल हैं। यह दशातों है कि निजी क्षेत्र और कॉर्पोरेट जगत, सरकारी नौकरियों जैसी सुरक्षा, वेतन, सुविधाएँ और पेंशन नहीं दे पाए हैं। क्या यह सब राज्य की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की विफलता का परिणाम नहीं है?

केंद्र स्तर पर भी, हमारे शिक्षा नीयोजनकताओं ने पाट्यक्रम और पाट्यसामग्री को रोजगार और अनौयिका से जोड़ने की दिशा में कभी गंभीर योजना नहीं बनाई। शिक्षा और रोजगार के बीच का यह अंतराल आज और भी गहरा हो गया है।

मेरी 87 वर्षीय माँ कहती हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की बातें सुनीं आई हैं – और यह भी कि पहले चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थीं। आज भी यही मुद्दे बने हुए हैं। युवावाणी पत्रिका में छपे एक लेख में समाजसेवी बच्चो सिंह बिष्ट लिखते हैं कि महिलाओं ने परंपरागत कृषि प्रणाली की रीढ़ की हड्डी बनकर काम किया है, लेकिन अब वे अपने अनुभवों से सीखकर बेडियों को पहने, नौकरी करने, और ऐसे जीववसाथी चुनने के लिए प्रेरित कर रही हैं जो सरकारी या स्थायी नौकरी में हों – ताकि उन्हें वही मेहनत और पौड़ा न सहनी पड़े जो उनकी माँओं ने झेली। गाँवों का खाली होना, एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण का संकेत भी है। ग्रामीण विकास में पंचायतों की मजबूत भागीदारी के लिए जरूरी है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अथ्यक्ष का सीधा चुनाव जनता करे – इससे भारतीय लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण और जनसहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। अब समय आ गया है कि आधिकारिक ढांचे को पुनर्विचार के दायरे में लाया जाए और वास्तविक शक्ति पंचायत राज संस्थाओं को सौंपी जाए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अब तक जितने भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं, वे आजीविका के टिकाऊ साधन देने में असफल रहे हैं। मेरा मोटा अनुमान है कि कोविड के दौरान गांव लौटे 95% से अधिक लोग अब फिर शहरों की ओर लौट चुके हैं।

गांधी जयंती के साथ संघ

के सौ साल! इस पर

लिखते हुए सबसे पहले जो

बात याद आती है वह यह है

कि क्या आज भी संघ और

भाजपा के लोगों की समझ

वही नहीं है जो किसी समय

संघ के और भाजपा के नेता

केदारनाथ साहनी की थी।

आरएसएस पर सबसे पहले

विस्तार से लिखने वाले

उसके पूर्व स्वयंसेवक

देसराज गोयल ने लिखा है

कि दिल्ली के मुख्य

कार्यकारी पार्षद केदारनाथ

साहनी ने बहुत सारे लोगों

के साथ स्वतंत्रता संग्राम

सेनानी और शेर झ ए–

दिल्ली कहलाने वाले चौधरी

ब्रह्मप्रकाश को भी एक

निमंत्रण पत्र भेजते हुए

उनसे आने का आग्रह

किया। निमंत्रण आरएसएस

की दिल्ली शाखा के वार्षिक

समारोह का था।

–अजीत द्विवेदी–

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें करीब सात करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या सात करोड़ 89 लाख थी, जो अब घट कर सात करोड़ 42 लाख हो गई है। इस आधार पर कह सकते हैं कि सिर्फ 47 लाख नाम घटे हैं। लेकिन असल में करीब 69 लाख नाम कटे हैं। यह सात करोड़ 42 लाख की जो संख्या दिख रही है उसमें साढ़े 21 लाख नाम ऐसे हैं, जो नए जोड़े गए हैं। सो, चुनाव आयोग ने अपनी ओर से एसआईआर का काम पूरा कर दिया है। अगले कुछ दिन में एक पूरक सूची आ सकती है, जिसमें कुछ और नए नाम होंगे। लेकिन सवाल है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने से सारे सवालों के जवाब मिल गए? इसको लेकर जितने संदेह थे, सब दूर हो गए? क्या अब सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा मामला बंद हो जाएगा या वहां नए सवाल खड़े होंगे?

ध्यान रहे एसआईआर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लौबत है। सर्वोच्च अदालत ने मतदाता के सत्यापन के एक दस्तावेज के तौर पर आधार को शामिल करने और जिन लोगों के नाम कटे थे उनके ऑनलाइन आवेदन लेने का जिस

नहीं बदला साल में औसतन दो-तीन पत्रकारों की हत्या का तथ्य

–सर्वमित्रा सुरजन–

पत्रकारिता को लेकर एक घुटन भरी स्थिति बनती जा रही है। एक तरफ सरकार का चाटुकारिता करने वाले पत्रकार हैं, और दूसरी तरफ जान हथेली पर लेकर चलने वाले पत्रकार हैं और साथ ही देश में ऐसे पत्रकार भी हैं, जिनकी आवाज कानून के फंदे में लेकर दबाने की कोशिशें चल रही हैं। कई ऐसे पत्रकार हुए, जिन्होंने किसी औद्योगिक समूह की सरकार से नजदीकियों पर रिपोर्टिंग की, तो उसे अपराध बता दिया गया।

उत्तराखंड में स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की 10 दिन की गुमशुदगी के बाद संदिग्ध हालात में मौत ने देश में पत्रकारों और पत्रकारिता की स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस साल की शुरूआत में छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसे ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई थी। पैटर्न ऐसे पत्रकारों की हैं, जिनकी आवाज कानून के फंदे में लेकर दबाने की कोशिशें चल रही हैं। कई ऐसे पत्रकार हुए, जिन्होंने किसी औद्योगिक समूह की सरकार से नजदीकियों पर रिपोर्टिंग की, तो उसे अपराध बता दिया गया।

उत्तराखंड में स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप की 10 दिन की गुमशुदगी के बाद संदिग्ध हालात में मौत ने देश में पत्रकारों और पत्रकारिता की स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस साल की शुरूआत में छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसे ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई थी। पैटर्न ऐसे पत्रकारों की हैं, जिनकी आवाज कानून के फंदे में लेकर दबाने की कोशिशें चल रही हैं। कई ऐसे पत्रकार हुए, जिन्होंने किसी औद्योगिक समूह की सरकार से नजदीकियों पर रिपोर्टिंग की, तो उसे अपराध बता दिया गया।

संघ के सौ साल में हासिल है मोदी के 11 साल!

सौ साल का संघ खुद को शक्तिशाली समझ सकता है। मगर बाहर की बात तो अलग है। खुद जिसे वह परिवार कहता है उसमें मोदी के सामने तो वह कमजोर साबित हो ही गया है। सरसंघचालक मोहन भागवत को 75 साल में रिटायर होने की बात कह कर बदलना पड़ा। केवल सांप्रदायिकता बढ़ाने के मामले में उसे और बीजेपी को सफलता मिली है। मगर सांप्रदायिकता बढ़ने से देश मजबूत हुआ है यह सिद्ध करना उसे मुश्किल साबित हो रहा है।

गांधी जयंती के साथ संघ के सौ साल! इस पर लिखते हुए सबसे पहले जो बात याद आती है वह यह है कि क्या आज भी संघ और भाजपा के लोगों की समझ वही नहीं है जो किसी समय संघ के और भाजपा के नेता केदारनाथ साहनी की थी। आरएसएस पर सबसे पहले विस्तार से लिखने वाले उसके पूर्व स्वयंसेवक देसराज गोयल ने लिखा है कि दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद केदारनाथ साहनी ने बहुत सारे लोगों के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शेर झ ए- दिल्ली कहलाने वाले चौधरी ब्रह्मप्रकाश को भी एक निमंत्रण पत्र भेजते हुए उनसे आने का आग्रह किया। निमंत्रण आरएसएस की दिल्ली शाखा के वार्षिक समारोह का था। जिसमें कहा गया था कि पधार कर संघ का और अधिक परिचय प्राप्त करें।

देसराज गोयल जिनका निधन अभी कुछ साल पूर्व ही हुआ उनकी किताब ह्र्माष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लिखी किताबों में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। गोयल जी अपनी किताब की शुरूआत ही इस वाक्ये से करते हैं। इसका पहला अध्याय है ह्यअज्ञान का इंसान लोकेट है। इसमें वे कहते हैं कि साहनीजी पुराने स्वयंसेवक थे। उनका वि्वास था कि लोग संघ की आलोचना तो विद्वेष के कारण करते हैं या नासमझी की वजह से। कोई भी व्यक्ति इस

एसआईआर के कई सवाल अब भी अनसुलझे

दिन आदेश दिया था उस दिन कहा था कि अगर गड़बड़ी मिली तो वह पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगी। पता नहीं अदालत की आगे की सुनवाई में क्या होगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी अनेक सवाल अनसुलझे रह गए हैं। इनका जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है और पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक इसका विरोध तेज हो गया है। केरल में तो विधानसभा में सर्वसम्मति से एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। सो, कह सकते हैं कि एसआईआर की एक परीक्षा अभी और होनी है।

बहरहाल, अब बिहार के एसआईआर के आंकड़े को देखने और उसके निहितार्थों को समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने जुलाई के अंत में जो मसौदा सूची जारी की थी उसमें 7.24 करोड़ नाम थे और 65 लाख 64 हजार नाम काट दिए गए थे। उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ लेकिन आयोग अपनी बात पर अड़ा रहा। आयोग ने कहा कि इसमें 22 लाख से कुछ ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिनका निधन हो गया दस्तावेज के तौर पर आधार की तथ्याी रूप से शिफ्ट कर गए हैं और साढ़े छह लाख के करीब लोगों के नाम एक से ज्यादा

पुण्य अवसर का लाभ नहीं उठाएगा यह बात साहनी जी के कल्पना से परे थी।

आगे की बात बताने से पहले हम यहां यह जरूर याद कर लें कि अभी मंगलवार 30 सितम्बर को ही दिल्ली में भाजपा और संघ को बनाने वाले साहनी जी के समकालीन विजय कुमार मल्होत्रा भी नहीं रहे। साहनी जी कुछ साल पहले नहीं रहे थे। ये दोनों नेता दिल्ली में भाजपा और संघ को समवाने वालों में थे। दोनों ही सब के साथ मिलकर काम करने वाले। आज की तरह सांप्रदायिक जहर से दूर। इनके साथ मदनलाल खुराना भी। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन किया। जैसे की बोलते हैं खुब लंबी चौड़ी बातें कीं। मगर कहीं देखने को नहीं मिला कि दिल्ली में भाजपा को खड़ा करने वाले इन नेताओं की भी तारीफ की।

खैर यह भाजपा और संघ के सोचने की बात है कि वे खुद को बनाने वाले नेताओं की याद क्यों नहीं करते हैं और कांग्रेस के नेताओं को ही ज्यादातर याद करते रहते हैं। सरदार पटेल हों या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भाजपा या संघ उन्हें ज्यादा याद करते हैं अपने नेताओं को कम।

बहरहाल साहनीजी जो सोच भी नहीं सकते थे वह हुआ। कुछ लोग आजादी के आंदोलन से निकले चौधरी ब्रह्मप्रकाश जैसे भी होते हैं। जिन्होंने निमंत्रण पत्र के उतर में लिखा कि आपने मुझे आरएसएस के वार्षिक समारोह में आने का निमंत्रण दिया जिसमें सरसंघचालक बालासाहब देवरस भी आ रहे हैं कि संघ के बारे में मेरी जानकारी बढ़े और गलतफहमी दूर हो जाए। क्या आपका ख्याल है कि अनुशासित प्रधान, परेड, शारिरिक व्यायाम को देखकर और उसके साथ घिसे पिटे उपदेश सुनकर कोई यकीन कर लेगा कि आरएसएस एक निरिह संगठन है? मैं मानवीय चेतना और बोध को उच्चतर

जगहों पर थे। यह हिसाब था 65 लाख 64 हजार लोगों के नाम कटने का। अब नाम कटने का आंकड़ा 69 लाख का है। सवाल है कि साढ़े तीन लाख के करीब जो नए नाम कटे हैं, वह किन लोगों के हैं? चुनाव आयोग ने इनको नॉट रिकमेंडेड की श्रेणी में रखा था और नोटिस जारी किया था। चुनाव

आयोग ने खुद ही बताया है कि बिना पक्ष सुने किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। सो, जाहिर है कि इन साढ़े तीन लाख लोगों का पक्ष सुन कर इनका नाम काटा गया होगा। अब इन सवाल है कि इनके दस्तावेजों में क्या गड़बड़ी भेजी है? क्या इनके पास आधार भी नहीं था? या आधार था लेकिन आयोग को उसकी प्रामाणिकता पर संदेह था?

ध्यान रहे अनेक लोगों की कहानियां आ रही हैं कि उनके पास सिर्फ आधार था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दम पर वे आधार के जरिए मतदाता बन गए। अगर साढ़े तीन लाख लोगों के पास आधार भी नहीं था या आधार था तो संदिध था तो चुनाव आयोग ने उनका क्या किया? क्या आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कोई जानकारी भेजी है? क्या उसने इन लोगों को संदिग्ध नागरिक की श्रेणी में रखा है? अगर ऐसा भी है कि बहुत से लोगों ने फॉर्म भर आ और नोटिस आने के बाद गायब हो गए तो उनकी भी जानकारी निश्चित रूप से

स्तर की चीज समझता हूं। ऐसे समारोहों के प्रदर्शन बच्चों या उन वयस्कों के लिए जो आरएसएस को नहीं जानते आकर्षक हो सकते हैं। मेरे जैसे लोग जो आरएसएस को जानते हैं इस पाखंडपूर्ण विनम्रता और अनुशासन से धोखा नहीं खा सकते।

चौधरी बह्मप्रकाश ने आगे लिखा कि आरएसएस के लोग अनुशासित हैं, विनम्रता दिखाने की भी ट्रेनिंग उन्हें मिली है। मगर साथ ही चरित्रननन के लिए कानाफूसी का अभियान चलाने की भी पूरी ट्रेनिंग है। विनम्रता पूर्वक नमस्ते करने वाले हाथों को असहमत व्यक्तियों को छुआ भोंकने की भी पूरी ट्रेनिंग है।

आज जब आरएसएस सौ साल का हो रहा है तब भी संघ के लोग वही कहते हैं कि सवाल उठाने वाले संघ को जानते नहीं। वे किसी सवाल का जवाब नहीं देते हमेशा इसी आड़ में छुपते हैं कि संघ को नहीं जानते। नेहरू ने भी यह बात कही थी, सरदार पटेल ने भी और गांधी जी ने भी। पहले गांधी जी की बात। क्योंकि संघ के सौ साल गांधी जयंती पर पूरे हो रहे हैं। गांधी जी ने क्या कहा था? संघ द्वारा प्रकाशित सामग्री में कहा जाता है कि गांधी जी ने इस संगठन की तारीफ की थी। मगर इतिहास में इसके कहीं प्रणाम नहीं मिलते। हां गांधी जी का यह कहा जरूर मिलता है कि जब उनसे किसी ने संघ के अनुशासन की तारीफ की तो उन्होंने कहा कि लेकिन भूलो मत कि हिटरर के नाजी और मुसोलिनी के फासिस्ट भी ऐसे ही थे। गांधी ने संघ को निरंकुश दृष्टि वाला और सांप्रदायिक संगठन कहा।

और बाद में गांधी जी की हत्या के बाद तो सरदार पटेल जिन्हें भी वे अपने पाले में खींचने की कोशिश करते रहते हैं तो साफ तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस पत्र के जवाब में जिसमें उन्होंने संघ की पैरवी की थी कहा था आरएसएस ने देश में ऐसा वातावरण बनाया कि ऐसी

केंद्रीय गृह मंत्रालय की दी जानी चाहिए, क्या आयोग ने ऐसा किया है? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं अन्यथा आगे जिन

राज्यों में एसआईआर होगा वहां भी मसौदा सूची में नाम होने के बावजूद लाखों लोगों के नाम अटिस सूची से बाहर हो जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिहार में जिन साढ़े तीन लाख लोगों के नाम मसौदा सूची में होने के बावजूद कटे हैं या तो वे विदेशी व संदिग्ध नागरिक हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं या इसी देश के नागरिक हैं लेकिन किसी तकनीकी आधार पर उनका नाम काट कर उनको चोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है? ये दोनों स्थितियां चिंताजनक हैं।

इसी से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने आधार को किस रूप में लिया? अगर किसी नागरिक की ओर से एक्मत्र पहचान पत्र के तौर पर आधार पेश किया गया तो उसे आयोग ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? उसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया गया या संदिध बता कर किसी और दस्तावेज की मांग की गई? इस सवाल का जवाब भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जिन राज्यों में एसआईआर होगा वहां ज्यादातर लोग आधार ही पेश करेंगे। इसके अलावा एक सवाल यह है कि मसौदा सूची

बंधकर दुखदायी घटना (गांधी जी की हत्या) संभव हुई। आरएसएस की गतिविधियों से सरकार और राज्य के अस्तित्व को ही खतरा हो गया था।

और तत्कालीन सरसंघचालक गोलवलकर के पत्र के जवाब में तो सरदार पटेल ने और स्पष्ट लिखा कि आरएसएस की सारी स्पीचेज सांप्रदायिक विष से भरी थीं। उस विष का परिणाम अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुबानी देश को सहना पड़ी। और सरदार पटेल विनयकी सबसे ऊंची मूर्ति प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में लगावाई है यह भी लिखा कि उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी।

उपर नेहरू का भी जिक्र किया था तो नेहरू ने क्या कहा? गोलवलकर के पत्र बैसे तो नेहरू सारे अपने गृहमंत्री पटेल को फारवर्ड कर देते थे मगर जब गोलवलकर उनसे मिलने के लिए लिख रहे थे तो नेहरु ने जवाब में लिखा कि मिलने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि आपके घोषित उद्देश्य कुछ और हैं वास्तविक कुछ और। ये वास्तविक उद्देश्य भारतीय संसद के निर्णय और प्रस्तावित संविधान के प्रावधानों के बिल्कुल विपरित हैं। हमारी सूचना के अनुसार ये गतिविधियां राष्ट्रविरोधी और प्रायः भीतरघाती तथ्य हिसापूर्ण होती हैं।

इतने सलों में क्या बदला है? सांप्रदायिक भाषणों के बाद अब तो धर्म के आधार पर खुले आम धमकियां दी जाने लगीं। प्रधानमंत्री से खम्बों के स्तर पर। पोस्टर बैनर लगने लगे मुसलमानों के खिलाफ! मुख्यमंत्री 7 पीढ़ियां बाद रखेंगी जैसे बयान देने लगे। उसी तरह पिढोगे कहने लगे। उसी उत्तर प्रदेश में जहां प्रधानमंत्री ने श्मशान और कब्रिस्तान में फर्क समझाया था। होली दीवाली और ईद में। क्या संघ जो भाजपा का मातृसंगठन है वहीं खड़ा है?

इतने सलों में क्या बदला है? सांप्रदायिक भाषणों के बाद अब तो धर्म के आधार पर खुले आम धमकियां दी जाने लगीं। प्रधानमंत्री से खम्बों के स्तर पर। पोस्टर बैनर लगने लगे मुसलमानों के खिलाफ! मुख्यमंत्री 7 पीढ़ियां बाद रखेंगी जैसे बयान देने लगे। उसी तरह पिढोगे कहने लगे। उसी उत्तर प्रदेश में जहां प्रधानमंत्री ने श्मशान और कब्रिस्तान में फर्क समझाया था। होली दीवाली और ईद में। क्या संघ जो भाजपा का मातृसंगठन है वहीं खड़ा है?

जारी होने के बाद चुनाव आयोग के सामने जो दावे और आपत्तियां आई थीं उनमें से कितने को और कैसे निपटया गया? यह सवाल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर का मुकदमा लड़ने वाले लोग बता रहे हैं कि आयोग के सामने जो आपत्तियां आई थीं उनमें 57 फीसदी ऐसी थीं, जिसमें लोगों ने अपना नाम काटने को कहा था। सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन लोगों ने मतगणना पत्रप्र भरा और मसौदा सूची में नाम आने के बाद खुद ही नाम कटवाने पहुंच गए?

इसी तरह दावा किया जा रहा है कि सात सौ लोगों ने अपने को विदेशी बता कर नाम काटने को कहा। यह कैसे हो सकता है? उनका फॉर्म कैसे स्वीकार हुआ और किन दस्तावेजों के आधार पर हुआ? सबसे मजेदार दावा यह है कि 28 लोगों ने दस्तखत करके आपति दर्ज कराई कि वे मर चुके हैं। क्या ऐसा होना संभव है? एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी अंतिम मतदाता सूची में 21.53 लाख लोगों के नाम जोड़े जाने की बात कही गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 7.24 करोड़ की मसौदा सूची में से 3.66 लाख नाम और काटे, जबकि 21.53 लाख नाम जोड़े तो अब कुल संख्या 7.42 करोड़ हो गई।

कई ऐसे पत्रकार हुए, जिन्होंने किसी औद्योगिक समूह की सरकार से नजदीकियों पर रिपोर्टिंग की, तो उसे अपराध बता दिया गया। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पत्रकारों ने मुख्यधारा के मीडिया से हटकर रिपोर्टिंग शुरू की, तो उसमें भी बहुत से पत्रकारों पर सरकार का चाबुक चला। अगर इससे भी काम नहीं बना तो विदेश से

वित्तीय सहायता, धनशोधन आदि के मामले बनाकर प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई या इनकम टैक्स को आगे किया गया। कई ऐसे पत्रकार भी सामने आए जिनमें स्थानीय पत्रकारों को सवाल पूछने पर भाजपा नेताओं ने डांटा कि हम तुम्हारे मालिक से शिकायत करेंगे। धमकी के तरह-तरह के रूप स्वतंत्र पत्रकारिता को कुचलने के लिए आजमाए जा रहे हैं। इसी वजह से विश्व में प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान काफी पीछे है।

2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 151वें स्थान पर रहा है, 2024 में मिले 159वें स्थान की तुलना में 8 पायदान भारत ऊपर चढ़ा, लेकिन उसका कोई असर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। बता दें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय विदेशी संस्था आरएसएसफ-रिपोर्टर्स गैरस्टाउट बॉर्डर्स द्वारा तैयार की जाती है। 2025 की रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर की गई टिप्पणी में लिखा है, '2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत की मीडिया एक 'अनौपचारिक आपातकाल' की स्थिति में आ गई है।

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का बड़ा बयान, लाशों से वोट डलवा रहे केरल की सत्ता में काबिज लोग

-कांग्रेस और वाम दलों पर मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण और विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री और मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लाशों ने चुना है, वे सालों से केरल में सरकार चला रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वे थिसुर में हुए विवाद पर चर्चा कर रहे थे। यहां कांग्रेस और वाम दलों पर मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगे थे। गोपी का दावा था कि केरल की मतदाता सूची में कई मरे हुए लोगों को भी सक्रिय वोटर दिखाकर शामिल किया गया था। केंद्रीय मंत्री गोपी पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने मतदाता सूची से छेड़छाड़ की थी। इस पर गोपी ने कहा, जो लोग जीतने के लिए लाशों से वोट डलवा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इतने समय से केरल में सत्ता में हैं। 125 साल पहले वफ़न हुईं लाशों से वोट डलवाए गए। आप सभी ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने थिसुर से जीत को लेकर कहा कि वह भाजपा के प्रभाव वाले पलक्कड़ या तिरुवनंतपुरम से नहीं जीते हैं। उन्होंने कहा, मैं थिसुर से जीता था, जहां भाजपा का ऐसा वर्चस्व भविष्य में भी नहीं हो सकता। मेरा मानना ​​है कि ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ थे। उन्होंने केरल की राजनीति में बदलाव की भी बात कही है।

क्रॉसिंग बंद तो शख्स बना शक्तिमान, कंधे पर बाइक रख पार की रेलवे लाइन

-वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया सज़ान, अब आरपीएफ करेगी कार्रवाई



झांसी (एजेंसी)। यूपी के झांसी में एक शख्स बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए शक्तिमान बन गया उसने अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर रेलवे लाइन पार कर ली। यह वीडियो झांसी-कानपुर रेलवे लाइन के पास मोट का बताया जा रहा है। बता दें झांसी-कानपुर रेलवे लाइन की क्रॉसिंग पर एक शख्स ने बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए अपनी बाइक को कंधे पर उठा लिया। इस वीडियो को किसी ने रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। वहीं वीडियो दो-तीन दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मोट थाना प्रभारी ने बताया कि बाइक को कंधे पर उठाकर ले जाने वाले शख्स का नाम प्रदीप है। वह समथर थाना क्षेत्र के कडूरा गांव का रहने वाला है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की लंबी कतार लगी थी और उन्ही समय इस शख्स ने ऐसा कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि मामला रेलवे क्रॉसिंग पार करने से जुड़ा है, इसलिए इस पर आगे की कार्रवाई आरपीएफ करेगी। पुलिस ने वायरल वीडियो का सज़ान लिया और तुरंत इसकी जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि यह घटना रेलवे सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला है। शख्स के खिलाफ अभी तक किसी तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है। बता दें इस तरह के वीडियो अक्सर लोगों को लापरवाही बरतने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उकसाते हैं।

त्रिपुरा में जेल से छह कैदी फरार

त्रिपुरा (एजेंसी)। उत्तर त्रिपुरा के धर्मनगर उप-जेल से बुधवार को छह कैदी फरार हो गए। इनमें से एक कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उत्तर त्रिपुरा के एसपी अविनाश कुमार राय ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर फरार कैदियों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट देवजानी चौधरी ने बताया कि आज सुबह करीब 6 बजे कैदियों को रोजमर्रा के कार्य और नारते के लिए सेल से छोड़ा गया था। तभी आचानक छह कैदियों ने जेल गार्ड गेड़ लिया पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और जेल के मुख्य द्वार से फरार हो गए। फरार कैदियों में सुनील देवर्मा उप्रकेद की सजा काट रहा था। घटना के बाद जिले के सभी पुलिस थानों को अलर्ट कर दिया गया है और सभी निकासी बिंदुओं को सील कर दिया गया है।

झाइवर ने खोया नियंत्रण, कार हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई, 6 की मौत

मुजफ्फरनगर (एजेंसी)। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक कार की ट्रक से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार तेज होने से झाइवर ने नियंत्रण खो दिया और वह हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। ट्रकर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे राहगीरों ने घायलों को बाहर निकाला। यह हादसा बुधवार का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इवहादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। दो घायलों को मेरठ रेफर किया गया, जहां एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में मरने वालों में तीन महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। यह पहली बार नहीं है जब यूपी में इस तरह का भीषण सड़क हादसा सामने आया है। बता दें इससे पहले 27 सितंबर को उज्जव में लखनऊ-अगरा एक्सप्रेसवे पर वृहत् भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी।

राजनाथ सिंह बोले- पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पूरा हिसाब-किताब बराबर

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए करीब चार महीने का वक्त बीत चुका है। भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शित की गई बीरता और साहस ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पूरा हिसाब-किताब बराबर कर लिया है। इन बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी में वायुसेना द्वारा आयोजित की गई एक संगोष्ठी में भारत के इस सैन्य अभियान को तीनों सेनाओं के बीच तालमेल का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिवेश में दुनिया में तेजी से बदल रही है, खतरे कहीं अधिक जटिल हो गए हैं। ऐसे में हमें ये स्वीकार करना होगा कि कोई भी सेना अलग-थलग होकर काम नहीं कर सकती है। किसी भी संघर्ष में कामयाबी के लिए अब अंतर संचालन और एकजुटता आवश्यक है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य

सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच एकजुटता और एकीकरण को बढ़ावा देना है। ये केवल एक नीतिगत मामला नहीं है। बल्कि तेजी से बदलते हुए सुरक्षा परिदृश्य के बीच अस्तित्व का भी एक प्रश्न है। एकजुटता का मार्ग संवाद, समझ और परंपराओं के सम्मान में शामिल है। तीनों सेनाओं को नई प्रणालियों का निर्माण करते समय एक-दूसरे की चुनौतियों का सम्मान करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से एकीकृत संचालन की तस्वीर, समय पर निर्णय लेने में सक्षमता, स्थिति आधारित जागरूकता में वृद्धि और अपने नुकसान के जोखिम को घटना जैसे बिंदु हमारे सामने आए हैं। उन्होंने वायुसेना की एकीकृत वायु कमान-नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस) की मिसाल देते हुए कहा कि इसने भारतीय सेना के आकाशतौर और नौसेना के त्रिगुण के साथ मिलकर काम किया। जो अभियान के समय पर एक संयुक्त संचालन का आधार बन रही है।

राजनाथ ने बताया कि युद्ध का विकसित

होता स्वरूप, पारंपरिक-गैर पारंपरिक खतरों के

जटिल अंतर्संबंध के साथ संयुक्तता को एक विकल्प की जगह पर संचालन से जुड़ी हुई एक बड़ी आवश्यकता बनाता है। वर्तमान समय में ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संचालन की प्रभावशीलता के लिए एक मूलभूत आवश्यकता बन गई है। जहां हमारी तीनों सेनाओं स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने में दक्ष हैं। वहीं, जमीन, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस की सबद्ध प्रकृति सहयोगात्मक शक्ति को विजय की सच्ची गारंटी बनाती है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि विमानन सुरक्षा, साइबर युद्ध जैसे अहम क्षेत्रों में मानकों में भिन्नता विनाशकारी साबित हो सकती है। निरीक्षण में छोटी सी भी गलती व्यापक असर पैदा कर सकती है। अगर हमारी साइबर रक्षा प्रणालियां सभी सेनाओं में अलग-अलग हैं तो विरोधी इस अंतर का फायदा उठा सकते हैं। हमें अपने मानकों में सामंजस्य स्थापित करके इन कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा। उन्होंने पीएम मोदी के हाल ही में कोलकाता में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को



संबोधित करते वक्त संयुक्तता व एकीकरण के महत्व पर दिए गए जोर वाली टिप्पणी को भी प्रमुखता से रेखांकित किया। साथ ही कहा कि इससे सरकार की मामले पर स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। जिसमें ये ध्यान दिया जा रहा है कि सशस्त्र बल न केवल मूल्यों और परंपराओं के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हों। बल्कि वो भविष्य के लिए तैयार प्रणालियों के अग्रदूत भी हों।

चिदंबरम के बयान से कांग्रेस में बवाल, राशिद अल्वी ने कहा, इससे बीजेपी को फायदा होगा

–बीजेपी का तंज सोनिया और राहुल गांधी जवाब दें

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के दावे पर कांग्रेस के अंदर बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस बयान को पार्टी को कमजोर करने वाला बताया। अल्वी ने कहा, क्या इसका मतलब है कि वे अमेरिकी दबाव में काम कर रहे थे? उनका यह बयान सिर्फ बीजेपी को फायदा देगा।

दरअसल, चिदंबरम ने दावा किया था कि 26/11 हमले के बाद भारत अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। साल 2008 में मुंबई में हमला हुआ, तब कांग्रेस नेता चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलिजा राइस और अमेरिकी प्रधानमंत्री मनमोहन से मिलने भारत आई थीं और उनसे स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का अनुरोध किया था। चिदंबरम का कहना था कि मेरे मन में बदला लेने का विचार आया था, लेकिन मनमोहन सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। चिदंबरम ने कहा, पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने आई



थी कि युद्ध मत शुरू कीजिए। उन्होंने आतंकी हमले के कुछ दिन बाद ही गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। मुंबई हमले में 175 लोगों की जान गई थी।

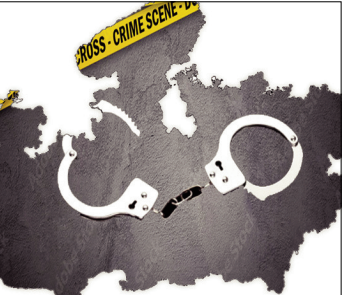
अब चिदंबरम के बयान पर कांग्रेस नेता अल्वी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अल्वी ने कहा, क्या इसका मतलब है कि वे अमेरिकी दबाव में काम कर रहे थे? ऐसा बयान केवल बीजेपी को फायदा देगा।

चिदंबरम अब 16 साल बाद यह दावा क्यों कर रहे हैं? अगर उस समय वे असहमत थे, तब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस के अंदर ही कई लोग हैं जो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। इसके पहले बीजेपी ने चिदंबरम के बयान पर तंज कसा था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मनमोहन सिंह सरकार को कमजोर करार देकर राहुल गांधी पर सवाल दोगे थे। प्रसाद ने कहा, मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री रहे चिदंबरम ने अब खुद माना है कि मुंबई हमलों के बाद वे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में थे, लेकिन उस समय विदेश मंत्रालय ने उन्हें रोक दिया और पूर्व पीएम सिंह चुप रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, यह कितनी कमजोर सरकार थी, जब निर्दोष भारतीय मारे जा रहे थे।

अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ 29 प्रतिशत बड़े अपराध, देश में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उनके हक के लिए ताल ठेककर दावा करने वाली सरकारों के लिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ पूरे देश में करीब 29 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं। जिन राज्यों में सर्वाधिक जुल्म और अत्याचार हुए हैं उसमें मणिपुर पहले और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मणिपुर इस मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा की आग अभी भी सुलग रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, वहां एसटी समुदाय के खिलाफ 3,399 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2022 में ऐसे मामलों की संख्या सिर्फ एक थी और 2021 में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो मणिपुर के बाद मध्य प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर



पर है। जहां एसटी समुदाय के खिलाफ अपराध के 2,858 मामले दर्ज किए गए हैं। आजादी के 78 सालों बाद भी देश के सबसे दबे-कुचले समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे बल्कि उसकी संख्या में और इजाफा हो रहा है। इस बात की तस्दीक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने की है। नवीनतम आंकड़ों के

अनुसार, देशभर में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध के मामलों में करीब 29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध के मामलों में 28.8 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2024 में एसटी समुदाय के खिलाफ देश भर में कुल 12,960 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2022 में यह संख्या 10,064 थी। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो मणिपुर के बाद मध्य प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पर है। जहां एसटी समुदाय के खिलाफ अपराध के 2,858 मामले दर्ज किए गए हैं। 2022 में यह संख्या 2,979 और 2021 में 2,627 थी। इसके बाद तीसरे स्थान पर राजस्थान है, जहां 2023 में ऐसे 2,453 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 के 2,521 मामलों से कम है, लेकिन 2021 में दर्ज 2,121 मामलों से अधिक है।

मानसून विदाई को गलत साबित कर रही दिल्ली और राजस्थान की भारी बारिश

–जयपुर में रावण के पुतले बहे, दिल्ली में जलभराव और जाप से लोग होते रहे परेशान

नई दिल्ली (एजेंसी)। कठने को देशभर में मंगलवार को ही आधिकारिक रूप से मानसून का समापन हो गया, लेकिन बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर और आसपास के इलाकों में मंगलवार को महज दो घंटे की तेज बारिश ने हालात बिगाड़ के ख दिए। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया और दशहरा उत्सव के लिए तैयार रावण के पुतले बहते नजर आए। आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस मानसून देशभर में सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है। यहां दिल्ली में भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित होता हुआ दिखा।

दरअसल मंगलवार को दिल्ली में मौसम ने अचानक करबट ली और दिनभर तेज वर्षा हुई, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जलभराव और जगह-जगह जाप से लोग परेशान होते रहे। इस बारिश ने गर्मी से राहत तो दिलाई लेकिन लोगों को परेशानी भी खूब हुई। यहां बुधवार और गुरुवार को भी वर्षा का अनुमान है। वहीं मानसून विदाई के बावजूद राजस्थान में हो रही बारिश सभी को हैरान कर रही है। यहां कोटा में 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला बारिश में भीग गया। दावा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दशहरे के दिन यानी 2 अक्टूबर को भी राजस्थान में तेज बारिश हो सकती है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इस बार जून से सितंबर तक के मानसून सीजन में देशभर में सामान्य से

8प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई। औसतन 868.6 मिमी वर्षा होती है, जबकि इस साल 937.2 मिमी दर्ज की गई। इस मानसूनी बारिश ने हालांकि खुशहाली के साथ-साथ तबाही लाने का भी काम किया है। आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून में मौसम से जुड़ी घटनाओं से करीब 1520 लोगों की जान चली गई। इनमें से 935 मौतें बाढ़ और भारी बारिश से हुईं, जबकि 570 लोगों की मौत बिजली गिरने और आंधी-तूफान की वजह से हुई। आईएमडी ने यह भी बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। अक्टूबर में सामान्य से 15 प्रतिशत ज्यादा वर्षा होने का अनुमान है। दक्षिण राज्यों तमिलनाडु, ओंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी मानसून के बाद सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है।

दिल्ली में बादल और हल्की बारिश की संभावना

राजधानी दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेंल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 38 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज दिनभर बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदवादी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में बारिश और हदसे

उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर और कानपुर सहित 36 जिलों में बुधवार बारिश का अलर्ट है। वाराणसी में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश रातभर जारी रही और बुधवार सुबह तक करीब 60 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश से लेोट्टा टीला

जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों पर फिर प्रहार... तहरीक-ए-हुरियत के मुख्यालय को कुर्क किया

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तहरीक-ए-हुरियत के मुख्यालय को कुर्क किया है, जिसकी स्थापना अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने 2004 में की थी। बीते साल बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूपीए) के तहत ऑफिस को कुर्क किया गया है। पुलिस ने कहा कि अलगाववादी और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, हैदरपुरा के रहमताबाद स्थित प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुरियत के मुख्यालय को कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्ति में एक तीन मंजिला इमारत शामिल है, जिसका इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठन के कार्यालय के रूप में किया जाता था। तहरीक-ए-हुरियत की स्थापना गिलानी ने अपने मूल संगठन जमात-ए-इस्लामी से अलग होने के बाद की थी। 2023 में, केंद्र ने तहरीक-ए-हुरियत को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया था। संगठन का मुख्यालय हैदरपुरा के रहमताबाद स्थित गिलानी के आवास परिसर में स्थित था। गिलानी और तहरीक-ए-हुरियत प्रमुख मोहम्मद अशरफ सेह्राई (जिनको 2022 में जम्मू की एक जेल में मृत्यु हो गई) के निधन और 2023 में इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद, यह अलगाववादी संगठन लगभग निष्क्रिय हो गया था। संगठन का अधिकांश शीर्ष और दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व जेल में है। पूर्व निर्वाचित विधायक गिलानी (92) अपने निधन के समय एक दशक से भी अधिक समय से नजरबंद थे। पुलिस ने कहा, एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर और सख्त प्राधिकारी से उचित अनुमति प्राप्त करके, कानूनी प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कुर्क की गई।

संघ संस्थापक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग

–बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली (एजेंसी)। आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के शताब्दी वर्ष में बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे ने संघ संस्थापक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार को राष्ट्र के लिए मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग कर दी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में सिद्दीकी ने डॉ हेडगेवार को स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र-निर्माता बताया है। उन्होंने देश की सेवा और युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना भरने में उनके योगदान का हवाला दिया है। संघ के शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है।

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय

अध्यक्ष सिद्दीकी ने कहा है, हेडगेवार के

योगदानों-स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी सक्रिय भागीदारी, राष्ट्र-निर्माण में उनके संगठनात्मक कोशल और एकजुट भारतीय समाज को लेकर उनके दृष्टिकोण को देखकर उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तितगत बलिदानों को मान्यता देगा, बल्कि सभी स्वयंसेवकों को राष्ट्र के लिए अथक कार्य करने के लिए भी प्रेरित करेगा। बात दें कि डॉ हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल, 1889 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। गुरुवार यानी 2 अक्टूबर, 2025 को इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संघ इन दिनों पूरे देश में अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। डॉ हेडगेवार संघ के संस्थापक सर संचालक थे। मोहन भागवत आरएसएस के छठे सर संचालक हैं।

आरएसएस के शताब्दी समारोह के मौके

पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के डॉ.

अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि संघ के हर संगठन का भाव एक है-राष्ट्र प्रथम। उनका कहना है कि संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण है। उन्होंने कहा कि संघ खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपता है।... संघ का एकमात्र लक्ष्य है.....एक भारत, श्रेष्ठ भारत। इस मौके पर पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया।

सांस्कृतिक-सामाजिक संगठन है आरएसएस

पीएम मोदी ने कहा कि परम पूज्य हेडगेवारजी ने 1925 में विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। हेडगेवार के देहांत के बाद युजी ने राष्ट्र सेवा के महान अभियान को आगे बढ़ाया। बता दें कि आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक-



सामाजिक संगठन बताया है, जिसके स्वयंसेवकों का लक्ष्य समाज में सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाना और नागरिकों में अनुशासन, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जगाना है।

एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में खुलासा, ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई

भुवनेश्वर (एजेंसी)। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट, फ़ाइम इन इंडिया 2023 ने ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बिगड़ती प्रवृत्ति का खुलासा हुआ है। 2023 में विभिन्न पुलिस थानों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 25,914 मामले दर्ज हुए हैं, जो देश में छठा सबसे अधिक है। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के 761 मामले दर्ज हुए, जो सबसे ज्यादा हैं। इसमें अश्लील कंटेंट भेजना, ब्लैकमेलिंग, मानहानि, फोटो के साथ छेड़छाड़ और फर्जी प्रोफाइल बनाना शामिल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि 1195 मामलों के साथ, ओडिशा उन शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है (सातवें स्थान पर) है। 2023 में ओडिशा और कर्नाटक में पोलोग्राफी के लिए बच्चों के इस्तेमाल और बाल पोलोग्राफी सामग्री के भंडारण से संबंधित 30 मामले दर्ज किए गए, जो देश में चौथे सबसे अधिक मामले हैं। ओडिशा में महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमले के 9,367 मामले दर्ज हुए, जो देश में चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस श्रेणी में ओडिशा की अपराध दर (40.6) देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा, ओडिशा में 2023 में महिलाओं के अपहरण और अगवा करने के 5,611 मामले दर्ज किए गए। इस श्रेणी में ओडिशा देश में सातवें स्थान पर है, लेकिन अपराध दर (24.3) के मामले में दिल्ली (39.5) के बाद दूसरा सबसे ऊंचा है।

नवमी कन्या पूजन के उपलक्ष में



मंजू कुमारी निमित्त सिंह आरव सिंह माता रानियां में अनीता बबोता सुनीता विनीता काजल अवनी

कल्याण वह रचना शिवानी मौजूद रही भैरव बाबा में कालू राहुल हनुमान जी आदि लोग मौजूद रहे।



मठ की दीवार गिर गई। जालौन में आकाशीय बिजली गिरने से 100 साल पुराना शिव मंदिर ढह गया। वहीं फतेहपुर में बिजली गिरने से छह लोगों की मौत हो गई।

इस तरह से भले ही मानसून का आधिकारिक समापन हो गया, लेकिन देश के

कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में प्रशासन और आम जनता दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि मौसम से होने वाले हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

केंद्र ने फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में पीआरआईपी योजना के तहत उद्योग और स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव किए आमंत्रित

नई दिल्ली 5,000 करोड़ रुपए के स्वीकृत परियंत्र के साथ, इस योजना से नई दवाओं, जटिल जैवसंरक दवाओं, बायोसिमिलर और नए विकसिता उपकरणों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए के कुल अनुसंधान एवं विकास निवेश वाली लगभग 300 परियोजनाओं को समर्थन देकर फार्मा-मैडेटेक इनोवेशन पायपलाइन को गति मिलने की उम्मीद है।

विभाग ने पहले अधिसूचित योजना में संशोधनों को अधिसूचित किया है और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित योजना के तहत, प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं के लिए, एमएसएमई और स्टार्टअप 5,000 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए 9 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए, उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप की 285 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाएं 100 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।

प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का पैमाना 1 करोड़ रुपए तक की लागत के लिए 100 प्रतिशत और 1 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त लागत का 50 प्रतिशत है, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक सीमित है।

बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का पैमाना परियोजना लागत का 35 प्रतिशत है, जो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक सीमित है।

इसके अलावा, उच्च-स्वास्थ्य स्वस्थ महत्व वाले लैबोरेटोरी अपेक्षाकृत कम बाजार क्षमता वाले क्षेत्रों में भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से, संशोधित योजना में प्रावधान है कि बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए सहायता 50 प्रतिशत तक हो सकती है, जो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक सीमित है।

ग्राहकों के लिए सुलभ है भारत की 5 सबसे सस्ती कारें

नई दिल्ली	और स्मूद राइड के कारण यह सबसे सस्ती डीसीटी कार बनी जाती है।	रुपए 11.16 लाख है। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ यह कार 17.18 केएमपीएल का माइलेज देती है।	इंटीरियर और आरामदायक राइड इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पसंदीदा बनाती है। हुंडई आई20 एनलाइन डीसीटी में भी 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स है। इसकी कीमत रुपए 10.23 लाख तक है। से रुपए 11.60 लाख तक है। कंपनी दावा करती है कि यह 20.2 केएमपीएल तक का माइलेज देती है।
पहले डुअल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) सुविधा महंगी कारों तक ही सीमित थी, लेकिन अब आम लोगों के लिए भी यह सुविधा हो गई है। इसकी शुरुआत टाटा अट्रोज डीसीटी करता है।	किआ सोनेट डीसीटी में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स मिलता है। इसकी कीमत रुपए 11.60 लाख से रुपए 13.65 लाख तक है और यह 18.31 केएमपीएल का माइलेज देती है।	नेक्सन 5-स्टार एनकैप सेफ्टी रेटिंग प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एसयूवी है, जो मददार रोड प्रेजेंस और फील्ड्स के साथ आती है। हुंडई वेन्यू डीसीटी 1.0 लीटर टर्बो इंजन और 7-स्पीड डीसीटी से लैस है। इसकी कीमत रुपए 10.93 लाख से शुरू होती है और यह 18.31 केएमपीएल तक का माइलेज देती है। प्रीमियम	इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पसंदीदा बनाती है। हुंडई आई20 एनलाइन डीसीटी में भी 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स है। इसकी कीमत रुपए 10.23 लाख तक है। से रुपए 11.60 लाख तक है। कंपनी दावा करती है कि यह 20.2 केएमपीएल तक का माइलेज देती है।
इसका एक्स-शोरूम प्राइस लगभग रुपए 9.42 लाख है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ यह कार 18 केएमपीएल तक का माइलेज देती है। मजबूत बिल्ड	स्टाईलिश डिजाइन और बेहतर टॉक इसे एसयूवी प्रेमियों में लोकप्रिय बनाता है। टाटा नेक्सन डीसीटी का एक्स-शोरूम प्राइस	रुपए 11.16 लाख है। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ यह कार 17.18 केएमपीएल का माइलेज देती है।	इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पसंदीदा बनाती है। हुंडई आई20 एनलाइन डीसीटी में भी 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स है। इसकी कीमत रुपए 10.23 लाख तक है। से रुपए 11.60 लाख तक है। कंपनी दावा करती है कि यह 20.2 केएमपीएल तक का माइलेज देती है।
सपोर्टी लुक, डुअल एर्रॉस्टर और ऑल-व्हेल इंटीरियर इसे युवाओं में खास बनाते हैं।			

जीएसटी 2.0 से उत्तर प्रदेश में विकास को मिली रफ्तार, पीतल से लेकर चमड़ा उद्योग को हो रहा फायदा

जीएसटी सुधार ने उत्तर प्रदेश की विविध अर्थव्यवस्था को लक्षित राहत प्रदान की है, जिसमें जीएसटी-एंपीक्यू कालीन, पीतल के बर्तन, जरादोजी, जूते, चीनी मेड्री के उत्पादन, खेल के सामान और सीमेंट शामिल हैं।

गुफ़हार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कम कर दरों से परिवारों के सामर्थ्य में सुधार होगा, कारीगरों पर कार्यशाला पूंजी का ख़ाब कम होगा और घरेलू तथा वैश्विक दोनों प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी। जीएसटी में टैक्स की दरें कम होने से भदोही के कालीन, मुद्राबाद के पीतल के बर्तन और सहारनपुर के लकड़ी के सामान के 6-7 प्रतिशत सस्ते होने की उम्मीद है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और लाखों कारीगरों के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

भदोही-मिर्जापुर-जौनपुर क्षेत्र भारत के सबसे बड़े हाथ से बुने और बुने हुए कालीन कलस्टर से एक है। जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत

सस्ते हो गए हैं। कानपुर-आगरा क्षेत्र में 15 लाख श्रमिकों को रोजगार देने वाले चमड़ा और फुटावियर कलस्टरों को भी जीएसटी दर में कटौती से लाभ मिलाया, जिससे एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और निर्यात में वृद्धि होगी। जीएसटी सुधारों से उत्तर प्रदेश में लकड़ी के खिलौने और शिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलाया, जो पारिवारिक कारीगरों द्वारा संचालित है, जिनमें से कई अपने घरों से काम करते हैं। केवल वाराणसी और चित्रकूट

25,000 कारीगरों को रोजगार देने हैं, जबकि सहारनपुर में लकड़ी को काम और नक्काशी में लगे हजारों कारीगर रहते हैं। रामपुर भी इस पारंपरिक शिल्प नेटवर्क का हिस्सा है। ये कलस्टर मेलों, धार्मिक खिलौनों और सजावट के माध्यम से मजबूत घरेलू मांग को पूरा करते हैं, और इनसे यूरोप और खाड़ी देशों तक मामूली निर्यात होता है। जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से खिलौने और छोटे शिल्प सस्ते होने की उम्मीद है।

रियलमी ने दिए संकेत, प्रशंसक की चाहत बढ़ी अब आगे क्या होगा

नई दिल्ली रियलमी ने एक बार फिर प्रशंसकों और तकनीक प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसने आगामी सहयोग के बारे में बातचीत और अटकलों को जन्म दे दिया है, जिससे प्रशंसक यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। पिछले कुछ सालों में रियलमी ने इनोवेशन को पाँच संस्कृति के साथ मिलाकर, नुमा दर्शकों के साथ प्रतिस्पर्धित होने वाले यद्वा अनुभवों का निर्माण करने वाले ब्रांड के रूप में अपनी छवि बनाई है। यह नया संकेत उसी दिशा में आगे बढ़ता है, जो अपनी कहानियों, पोपॉकॉप पात्रों और शक्ति के प्रतिष्ठित प्रतीकों के लिए प्रसिद्ध एक ऐसे युनिर्स के साथ साझेदारी का सुझाव देता है। मोडिया रिपोर्ट के मुताबिक वॉंग द्वारा साझा किया गया यह वाक्यांश महत्वाकांक्षी युद्ध, शक्तिशाली राजेशों और ऐसी दुनिया की कल्पना को उजागर करता है जहाँ शर्णीति, डिजाइन और नियति एक साथ आते हैं, यह संकेत देता है कि यह सहयोग जितना कल्पनाशील है, उतना ही मनोरंजक भी हो सकता है। रियलमी और सीडी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन समर्थन और शब्दों के चयन ने प्रशंसकों और मीडिया को अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया है कि यह ब्रांड के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी सहयोगों में से एक हो सकता है। ब्रांड का दृष्टिकोण न केवल तकनीक के प्रति, बल्कि ऐसे अनुभव बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो कल्पना को पकड़ें और दुनिया भर के दर्शकों से गहराई से जुड़ें। प्रशंसकों को रियलमी के सोशल चैनलों को बारिकी से फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में और भी नए आश्चर्य और संकेत सामने आने की उम्मीद है। यह संभावित सहयोग रियलमी के उस दृष्टिकोण के रेखांकित करता है जिसमें तकनीक को संस्कृति के साथ मिलाकर ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जो अभिनव और अविस्मरणीय दोनों हैं।

सरकार ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को तोड़ने के लिए 25 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज को जारी किए नोटिस

नई दिल्ली

फाइनेंशियल इंटेल्जेंस यूनिट ऑफ इंडिया (एफआईयू - आईएनडी) ने 25 ऑफशोर क्रेप्टो एक्सचेंज को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करने के लिए नोटिस भेजा है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से बयान में दी गई। ये नोटिस प्रेषेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 13 के तहत जारी किए गए थे। यह धारा अधिकारियों को जांच शुरू करने, कंपनी के रिकॉर्ड की जांच करने, शास्त्र विवरणों का सत्यापन करने और संदिग्ध लेनदेन पर रिपोर्ट मांगने का अधिकार देती है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिन 25 विदेशी कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें सिंगापुर की कांइनस्ट्यू, यूके की बीटीसीसी, हांगकांग की चांगेली और अमेरिका की पैक्सफुल शामिल हैं। अन्य कंपनियों में कंबोडिया की हूडइन, अमेरिका और यूके की सीईएक्सडॉटआईओ, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की एलबैंक, सेंट लूसिया की प्राइमएक्सबीटी, हांगकांग की कांइनएक्स, सिंगापुर की रेमीटानो, बोस्टन की पोनोमिएक्स, सेशेल्स की बिटमैक्स और लिक्टेस्ट्री की एफसीएक्सएस शामिल हैं। फाइनेंशियल इंटेल्जेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अलग-अलग नोटिस भी जारी किए हैं, जिनमें पीएमएलए के तहत उचित प्रतीकरण के बिना भारत में चल रहे ऐप्स और वेबसाइटों को हटाने का अनुरोध किया गया है। फाइनेंशियल इंटेल्जेंस यूनिट ऑफ इंडिया की स्थापना 2004 में की गई थी। यह सार्वजनिक वित्त लेनदेन के बारे में जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए नियोजित मध्य एशियाई है। मौजूदा समय में 50 क्रेप्टो वॉलेट फाइनेंशियल इंटेल्जेंस यूनिट ऑफ इंडिया के पास पंजीकृत हैं। हालांकि, कई विदेशी कंपनियां बिना पंजीकरण के भारत में काम कर रही हैं,

करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए 9 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।	करोड़ रुपए तक सीमित है। बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का पैमाना परियोजना
---	--

बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए, उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप की 285 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाएं 100 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।

प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का पैमाना 1 करोड़ रुपए तक की लागत के लिए 100 प्रतिशत और 1 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त लागत का 50 प्रतिशत है, जो अधिकतम 5	स्वास्थ्य सुरक्षा ढाँच का मजबूत करने के उद्देश्य से, संशोधित योजना में प्रावधान है कि बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए सहायता 50 प्रतिशत तक हो सकती है, जो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक सीमित है।
---	--

करोड़ रुपए तक सीमित है।

परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का पैमाना परियोजना लागत का 35 प्रतिशत है, जो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक सीमित है।

सर्वजनिक स्वास्थ्य महत्व वाले लेकिन अपेक्षाकृत कम बाजार क्षमता वाले क्षेत्रों में भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से, संशोधित योजना में प्रावधान है कि बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए सहायता 50 प्रतिशत तक हो सकती है, जो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक सीमित है।

इटीरियर और आरामदायक राइड
इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में
पसंदीदा बनाते हैं। हुंडई आई20
एनलाइन डीसीटी में भी 1.0
लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7-
स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स है
इसकी कीमत रुपये 10.23 लाख
से रुपये 11.60 लाख तक है।
कंपनी दावा करती है कि यह
20.2 के एमपीएल तक का
माइलेज देती है।

स्पोटी लुक, डुअल एजेंसि और ऑल-ब्लैक इंटीरियर इस युवाओं में खास बनाते हैं।

मेक इन इंडिया खतरे में 0 % GST ने भारतीय नोटबुक उद्योग को किया बर्बाद

शिक्षा को सस्ता करने का फैसला बना अभिशप, कच्चे आसाल पर 18% टैक्स और मासिक पायदान पर शून्य इन्सूटी से लाखों रोजगार संकट में

मुंबई/इंदौर

एक तरफ भारत सरकार जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत आर्थिक विकास का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्गट इंडिया नोटबुक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (ASEAN) मूक व्यापार समझौते के घातक संयोजन पर कड़ई चिंता जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि यह नीति भारतीय नोटबुक उद्योग के लिए विनाशकारी साबित हो रही है और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया संकल्प के विपरीत है। कर प्रणाली का घातक असंतुलन एसोसिएशन ने सरकार को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि नोटबुक पर 0 व जीएसटी और आसियान एफटीए के तहत इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों से आयातित नोटबुक पर 0% करस्टम ड्यूटी के कारण यह उद्योग अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। ड्यूटी-मुक्त आयात 0% जीएसटी के कारण, इन आयातित उत्पादों पर

जैसे पेपरबॉर्ड, गोंद, तार, पैकेजिंग सामग्री आदि पर 18 व जीएसटी वहन कराना पड़ता है, लेकिन उत्पाद पर 0% जीएसटी होने के कारण उन्हें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलता। लागत में वृद्धि नोटबुक निर्माण में उपयोग होने वाला केंद्र पेपरबॉर्ड जिस पर पहले 12% जीएसटी था, अब बढ़कर 18% हो गया है, जिससे घरेलू उत्पादन की लागत और बढ़ गई है। रोजगार और MSME पर सीधा हमला यह उद्योग मुख्यतः श्रम-प्रधान और लघु-स्तरीय (MSME) है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार देता है। इंडोनेशिया जैसे दुनिया के सबसे बड़े पत्र उत्पादक देशों से सस्ते आयात की बाढ़ ने भारतीय उद्योगों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, निवेश का नुकसान, और विदेशी मुद्रा पर प्रतिकूल असर पड़ना निश्चित है।

**इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कॉम से
1.41 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद:
केन्द्र**

नई दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) से 1.41 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह योजना जनताते समान रूप से बड़े पकिलकला 91,600 से करीब 1.5 गुना है। यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से गुवागार को दी गई। केंद्र सरकार को एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा कि ईसीएमएस के तहत सरकार को 1.15 लाख करोड़ रूप के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो तय लक्ष्य 59,350 करोड़ रूप से करीब दो गुना है। ईसीएमएस के लिए एप्लीकेशन विंडो 30 सितंबर को बंद हो गई है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग इंडोस्ट्रियस में बड़े निवेश आकर्षित करना, क्षमता विकसित करने के घेरुल मूल्य संवर्धन (डीएवी) और आर्थिकी कर्पनीयों को गुलबत वैल्यू चेन (जीवीएस) के साथ इंटीग्रेट करके एक मजबूत क्लोस्ड इंकोरपोरेट विकसित करना है। इस स्कीम में सरकार द्वारा भारतीय मैनुफैक्चरर्स को विभिन्न श्रेणियों के कंपोनेंट्स और सब-असेंबली के लिए अलग-अलग तरह के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे टेक्नोलॉजिकल क्षमताएं और स्कैल को हासिल कर पाएं।

ईएसआईसी ने अदालती मामलों के निपटारे के लिए नई एमनेस्टी योजना के दिशानिर्देश जारी किए

एनआईटीईएस का आरोप, टीसीएस ने पुणे में 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया

नई दिल्ली नैसेंट आईटी एम्प्लॉइज सीनेट (एनआईटीईएस) ने टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) पर आरोप लगाया है कि कंपनी पुणे में करीब 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही है। एनआईटीईएस एक फोरम है, जो कि आईटी सेक्टर के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह आरोप एनआईटीईएस के अध्यक्ष हरप्रोत सिंह सलूजा द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे गए पत्र में लगाया गया है, जिसमें प्रभावित कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। एनआईटीईएस के अनुसार, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने महाराष्ट्र के श्रम सचिव से इस मामले की जांच करने को कहा है। हालांकि, सलूजा ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति और भी खराब हो गई है, हाल के हफ्तों में पुणे में हजारों कर्मचारियों को कथित तौर पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। एनआईटीईएस ने दावा किया कि इसमें से कई कर्मचारी मध्यम से वरिष्ठ स्तर के पोसेवर हैं, जिन्होंने टीसीएस में 10 से 20 साल बिताए हैं, और ज्यादातर की उम्र 40 साल से अधिक है। एनआईटीईएस ने कहा कि मौजूदा बाजार में नई नौकरियां ढूँढना उनके लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनके पास होम लोन, स्कूल की फीस और बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसी वित्तीय जिम्मेदारियां हैं।

ओएसएम ने दुनिया का पहला बिना ड्राइवर वाला इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर किया लॉन्च

**चेयरमैन बोले-अब ऑटोनोंमस
व्हीकल कोई सपना नहीं, बल्कि
आज की जरूरत**

नई दिल्ली

भारतीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में आज इतिहास रच दिया। ओमेगा गा सीक्री मोबिलिटी (ओएसएम) ने दुनिया का पहला ऑटोनॉमस यानी बिना ड्राइवर वाला इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए से शुरू है। ये व्हीलर अब कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार है। मोडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओएसएम ने इस थ्री-व्हीलर का नाम 'स्वयंगति' रखा है। इसे ओएसएम के इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म और एआई-आधारित ऑटोनॉमी सिस्टम पर तैयार किया गया है।

यह शॉर्ट-डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जैसे एयरपोर्ट, स्मार्ट कैफे, इंडस्ट्रियल पार्क, गेटेड ड कम्प्युनिटी और भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में बिना ड्राइवर के चल सकेगा। वाहन को पहले से मैपिंग करके सेट किया जाता है, ताकि वह तय किए गए रास्ते पर सुरक्षित और सुचारु रूप से चल सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक ऑटोनॉमस वाहन बाजार 2030 तक 620 बिलियन डॉलर से

करेगा। भारत जैसे देश में जहां ट्रैफिक और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चुनौती है, वहां यह तकनीक सुरक्षित और किफायती समाधान लेकर आई है।

ओएसएम के फाउंडर और चेयरमैन ने कहा कि स्वयंगति का लॉन्च सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि भारत के ट्रांसपोर्टेशन भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है।

अब ऑटोनॉमस व्हीलर कोई सपना नहीं, बल्कि आज की जरूरत है। यह साबित करता है कि एआई और लिडार जैसी तकनीकें भारत में देश के लिए और सस्ती कीमत पर बनाई जा सकती हैं। ओएसएम के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर ने कहा कि हमारा मकसद ऑटोनॉमी को डेमोक्रेटाइज करना है। स्वयंगति न दिखाया है कि ईवी ड्रैफ्ट्स में इंटेलिजेंट सिस्टम्स को अब रोजमर्रा की मोबिलिटी में लाया जा सकता है। स्वयंगति ने हाल ही में 3 किमी की ऑटोनॉमस स्टूटेस्टिंग पूरी की, जिसमें 7 स्टॉप, रीसल-टाइम ऑब्स्ट्रकल डिटेक्शन और पैसेंजर सेफ्टी शामिल थी।

**इस साल यूपीआई लेनदेन की संख्या
31 फीसदी बढ़कर 19.63 अरब पहुंची**

नई दिल्ली इस साल सितंबर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की संख्या 31 फीसदी बढ़कर 19.63 अरब हो गई है। साथ ही इन लेनदेन की वैल्यू सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 24.90 लाख करोड़ पर पहुंच गई। यह जानकारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन (एनपीसीआई) ने दी। एनपीसीआई के मुताबिक औसत प्रति दिन लेनदेन की वैल्यू सितंबर में बढ़कर 82,991 करोड़ पर पहुंच गई, जो कि अगस्त में 80,177 करोड़ रुपए थी। सितंबर में प्रति दिन औसत 65.4 करोड़ लेनदेन हुए, जो कि अगस्त में औसत 64.5 करोड़ थे। इससे पहले अगस्त में यूपीआई ने पहली बार 20 अरब मासिक लेनदेन का आंकड़ा पार किया था। 2 अगस्त को रिकॉर्ड 70 करोड़ से ज्यादा लेनदेन हुए थे। इसके अलावा एनपीसीआई ने पर्सन-टू-मर्चेन्ट (पी2एम) लेनदेन की कुछ श्रेणियों के लिए लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए 24 घंटों के लिए कर दिया है। हालांकि एनपीसीआई ने पर्सन-टू-पर्सन के लिए लिमिट को एक लाख रुपए प्रति दिन पर बरकरार रखा था। अब एक लेनदेन में 5 लाख रुपए तक के क्रैडिट कार्ड बिल का भुगतान यूपीआई के जरिए करने की अनुमति है, हालांकि 24 घंटे की सीमा 6 लाख रुपए तक की गई है। नए फ्रेमवर्क के तहत केपिटल मार्केट और इश्योर्स पेमेंट के लिए प्रति लेनदेन सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि दैनिक सीमा 10 लाख रुपए है। सरकारी ई-मार्केट प्लेस लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन कर दी गई है। यात्रा बुकिंग, ऋण चुकोती और ईएमआई संघर्ष के लिए प्रति लेनदेन सीमा भी एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।

स्पोयर टायर हटाना शुरू कर दिया टाटा मोटर्स

नई दिल्ली केंद्रीय मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव करके साल 2020 में सरकार ने यह प्रावधान किया था कि पैसेंजर व्हीकल को स्पेयर टायर के साथ बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, यदिल उसमें ट्यूबलेस टायर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और पंचर रिपेयर किट मौजूद हो। उस समय यह बदलाव थोड़ा असामान्य लगा, लेकिन पांच साल बाद यह प्रथा धीरे-धीरे न सिर्फ प्रीमियम कारों में बल्कि मुख्यधारा की कारों में भी आने को हाई है। यूरोपीय बाजारों में यह वर्षों से चलन में है। टाटा मोटर्स ने अपनी छोट्टी इलेक्ट्रिक कारों जैसे पंच ईवी और रियागो ईवी के साथ-साथ हैरियर और सुफारी पर भी स्पेयर टायर हटाना शुरू कर दिया है। वहीं, मारुति सुजुकी ने फॉरेस्टर और ग्रेड विटारा के कुछ ईवीएट्स से स्पेयर हटाया है। उल्लेखनीय है कि सभी वैरिएंट से स्पेयर टायर हटाने का पहला काम मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने किया। कार से स्पेयर टायर हटाने के पीछे कई कारण हैं। सड़कों की स्थिति में सुधार, बेहतर टायर गुणवत्ता, टीपीएमएस और पंचर रिपेयर किट जैसी तकनीक, और टायर रिपेयर की दुकानों की उपलब्धता इसे संभव बना रही हैं। जिसके अलावा, स्पेयर टायर हटाने से वाहन का वजन कम होता है, इससे ईंधन दक्षता बढ़ती है और स्पेस का उपयोग सीएनजी सिलेंडर जैसे विकल्पों के लिए किया जा सकता है। हालांकि, कुछ कार मालिकों को यह बदलाव पसंद नहीं है, क्योंकि स्पेयर टायर लंबे समय से मोटरिंग सुरक्षा का अहम हिस्सा रहा है। फिर भी, बेहतर क्वालिटी के टायर और टीपीएमएस जैसी तकनीकें अब पहले ही प्रेशर में कमी आने की सूचना दे देती हैं।

चालू वित्त वर्ष में आरबीआई से नीतिगत दर में एक और कटौती की उम्मीद: रिपोर्ट

नई दिल्ली किसिल की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, जोएसटी दरों में दिखे और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण इस वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति वृद्धि का मुख्य विषय नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा दरों में कटौती की शुरुआत ने आरबीआई के लिए दरों में कटौती की गुंजाइश बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेड ने सितंबर में नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। एएफएंडपी ग्लोबल की उम्मीद है कि कैलेंडर वर्ष 2025 के बाकी बचे समय में 25 आधार अंकों की दो और कटौती की जाएगी और हमें चालू वित्त वर्ष में आरबीआई द्वारा एक और दर कटौती की उम्मीद है। जोएसटी सुधार से मुद्रास्फीति में रहत मिलने की संभावना है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्पादक इस कटौती का लाभ उपभोक्ता कीमतों पर कब डालते हैं। खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की जोएसटी में कटौती की गई है, जिससे मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी आने की संभावना है। प्रमुख खरीफ फसल उत्पादक राज्यों में अत्यधिक बारिश के कारण खाद्य मुद्रास्फीति को जोड़ियम का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद, पर्याप्त जलाशय स्तर रबी उत्पादन के लिए अच्छा संकेत है।



सिनेमा के बारे में मुझे उन्होंने ही सबकुछ सिखाया, संजय लीला भंसाली की तारीफ में बोले रणबीर

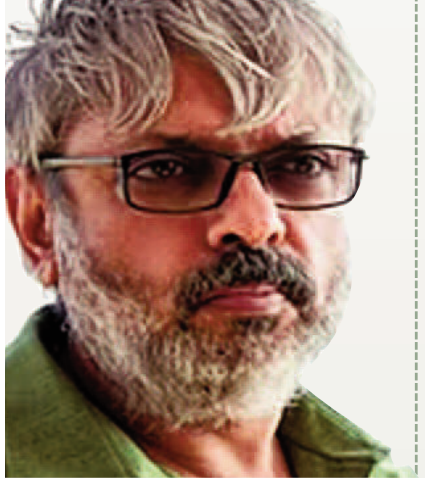
अभिनेता रणबीर कपूर ने साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से डेब्यू किया था। अब वे भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आएंगे। इस फिल्म के जरिए रणबीर कपूर करीब 18 साल बाद संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहे हैं। लाइव सेशन में की रणबीर ने फैंस से बात न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली की तारीफ करते हुए कहा कि अभिनय के बारे में वे जो कुछ भी जानते हैं, वह भंसाली ने ही उन्हें सिखाया है। दरअसल, रणबीर कपूर ने 28 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ लाइव सेशन आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने अपने को-एक्टर्स और निर्देशक भंसाली के बारे में बात की।

अगले साल रिलीज होगी लव एंड वॉर

फिल्म लव एंड वॉर 20 मार्च, 2026 को रिलीज होगी। इसमें रणबीर के अलावा आलिया भट्ट और विकी कोशल भी नजर आएंगे। फिल्म लव एंड वॉर के निर्देशन की कमान संजय लीला भंसाली ने संभाली है। रणबीर ने कहा, इस फिल्म में मेरे दो पसंदीदा हैं। एक, विकी कोशल। इसके अलावा मेरी सुपर टैलेंटेड वाइफ आलिया भट्ट।

भंसाली को बताया अस्ताद

रणबीर ने आगे कहा, इस फिल्म का निर्देशन वह शख्स कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे सिनेमा के बारे में सबकुछ सिखाया। अभिनय के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूँ, वह उन्हीं की देन है और उस समय वे एक उस्ताद थे। मैं उनके साथ 18 साल बाद काम कर रहा हूँ। आज वे और भी बड़े उस्ताद हैं। इसलिए मैं इस सहयोग से बहुत खुश हूँ। बता दें कि इस फिल्म में रणबीर पहली बार विकी कोशल के साथ काम कर रहे हैं।



सनी संसारी की तुलसी कुमारी में सान्या मल्होत्रा का बोल्ड नया अवतार!

अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा अपनी आगामी फिल्म सनी संसकारी की तुलसी कुमारी में अपने नए बोल्ड अवतार से सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। अपनी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली, सान्या ने एक निडर और फेंश लुक लेकर आ रही है जो फिल्म के जीवंत और बेबाक मूड को पूरी तरह कॉम्प्लिमेंट करता है। यह नया अवतार पहले से ही ट्रेंड कर रहा है। फैंस उनके आत्मविश्वास, ग्लैमर और स्वेग की खूब तारीफ कर रहे हैं। चाहे वो उनका

स्टाइलिश बीचवियर हो या कैमरे के सामने उनका बेबाक अंदाज — सान्या का यह नया लुक वाकई में विजुअल ट्रीट है। जिसने फिल्म सनी संसकारी की तुलसी कुमारी को इस सीजन की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बना दिया है। 'मिसेज' में अपने गहराई से भरे अभिनय से दिल जीतने के बाद, सान्या इस समय अपने करियर के सबसे यादगार साल का आनंद ले रही हैं। उनकी अनोखी और सामाजिक व्यंग्य पर बनी फिल्म 'कटहल-अ जैकफरुट मिस्ट्री' को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है, जो यह साबित करता है कि सान्या न सिर्फ अलग और दमदार सिनेमा की पैरोकार हैं, बल्कि लगातार अपनी कला से दर्शकों को चौंका रही हैं। इस पोस्ट में सान्या एक शानदार नीली बिकिनी पहने नजर आ रही हैं, और अभिनेत्री के प्रशंसक और फॉलोअर्स उनके आत्मविश्वास से भरे बदलाव की चर्चा कर रहे हैं। वरुण धवन, जान्हवी कपूर और रोहित सराफ के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए, सान्या का नया सिजलिंग लुक उनके अब तक के पिछले स्टाइल से बिल्कुल अलग बदलाव दिखाता है, जो उनके व्यक्तित्व का एक ग्लैमरस और बिंदस रूप दर्शाता है।

पब्लिसिटी में दम लगा रहे वरुण और जाह्नवी

फिल्म 'सनी संसकारी की तुलसी कुमारी' को हिट कराने के लिए वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ जमकर मेहनत कर रहे हैं। अब रोहित सराफ ने वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा को टैग कर वीडियो पोस्ट की है, जिसमें पांचों स्टार्स लगजरी कार की सवारी कर रहे हैं और कार में भी मस्ती करने का मौका नहीं गंवा रहे। वीडियो में सभी लोग अपने ही फिल्म के गाने बिजुरिया पर गजब के एक्सप्रेशन के साथ डांस कर रहे हैं लेकिन सारी लाइमलाइट मनीष पॉल लुट लेते हैं, क्योंकि वीडियो के आखिर में भी एक्टर कॉमेडी ही कर रहे हैं।

बीते रविवार से ही फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है

फिल्म 'सनी संसकारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म के लिए फिल्मों गुरुवार मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसी तारीख को ऋषभ शेट्टी अभिनीत कांतारा- वेंटर 1 भी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये एक पैन इंडिया फिल्म है और कई

भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म लगभग 125 करोड़ के बजट के साथ बनी है, जबकि 'सनी संसकारी की तुलसी कुमारी' का बजट लगभग 60 करोड़ है। अब देखना होगा कि पहले दिन कौन सी फिल्म दर्शकों का दिल जीतेगी और बड़ी कमाई करेगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो वरुण धवन और जान्हवी कपूर की ये साथ में दूसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों को बवाल में देखा गया था। फिल्म ने औसत कमाई की थी लेकिन ओटीटी पर फिल्म को अच्छा रिसांस मिला था।



नवरात्रि खुद को खोजने का पर्व, देवी हमारी हर सांस में हैं

बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने नवरात्रि को खुद को खोजने का पर्व बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर माता की चौकी का एक वीडियो शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि नवरात्रि का पर्व उनके लिए क्या मायने रखता है। तमन्ना भाटिया ने अपनी इस पोस्ट में लिखा, नवरात्रि केवल भक्ति की नौ रातें नहीं हैं, बल्कि यह खुद में लौटने, खुद को खोजने के नौ मौके भी हैं। हर शाम हमें याद दिलाती है कि देवी केवल मंदिरों या त्योहारों में ही नहीं, बल्कि हमारी हर सांस में हैं। उन्होंने आगे लिखा, दुर्गा हमें उन लड़ाइयों का सामना करने की हिम्मत देती हैं, जिनसे हम कतराते रहे हैं। लक्ष्मी हमें प्रचुरता को अपनाना सिखाती हैं—न सिर्फ धन की, बल्कि प्रेम, करुणा और अवसरों की भी। सरस्वती हमें सत्य बोलने और अनिश्चितता में बुद्धिमानी से निर्णय लेने की स्पष्टता देती हैं। काली उन भय, आदतों और पुरानी कथाओं को भस्म कर देती हैं, जो हमें सीमित रखती हैं। 'स्त्री-2' अभिनेत्री ने आगे लिखा, जब हम मां के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हम जीवन से चमत्कार मिलने

का इंतजार करना बंद कर देते हैं और उन्हें अपने कर्मों में ढूँढ़ने लगते हैं। बात यह नहीं है कि हम कितने अनुष्ठान करते हैं, बात यह है कि उन नौ रातों को चुपचाप हमारे खुद को देखने के तरीके को फिर से लिखने दें। इस नवरात्रि हर दीया न केवल उस देवी के लिए जलाए जिसकी आप पूजा करते हैं, बल्कि उस देवी के लिए भी जो आप पहले से ही हैं। समर्पण करते रहे। वर्क फ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया हाल ही में डायना पेंटी के साथ वेब सीरीज डू यू वाना पार्टनर में नजर आई थीं। इस सीरीज में जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफी मोतीवाला और रणविजय सिंह जैसे सितारे भी दिखाई दिए।



भागवत के प्रोड्यूसर हैं हरमन बावेजा



निर्माता हरमन बावेजा ने कहा, बावेजा स्टूडियोज में हमारा प्रयास हमेशा से ऐसी कहानियों पर आधारित रहा है जो साहसिक, प्रासंगिक और भावनात्मक रूप से ध्यान खींचती हों। भागवत इस कमिटमेंट का एक आदर्श उदाहरण है। यह सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है— यह मानव स्वभाव के अंधकारमय हिस्से की एक यात्रा है, जहां प्रेम, छल और न्याय का टकराव होता है।



फिल्म भागवत में जितेंद्र संग अरशद वारसी लगाएंगे तड़का

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी अब एक बार फिर से नए अवतार में पर्दे पर दिखाई देंगे। पहले वह जॉली एलएलबी 2 में वकील और फिर बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन गफूर के किरदार में दिखाई दिए। और अब वह पुलिस के रोल में नजर आने वाले हैं। वह पंचायत के



सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे। दोनों एकसाथ पहली बार स्क्रीन पर दिखेंगे। उनकी मूवी भागवत का पहला पोस्टर शनिवार, 27 सितंबर को जारी किया गया। इस काइम-थ्रिलर मूवी का पोस्टर शेयर करते हुए जी5 ने सोशल मीडिया पर लिखा, और हमें लगा था कि 2025 के सारे ट्विस्टर खत्म हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्टर आ गया है। भागवत आपके होश उड़ा देने आ रही है।

सच्ची घटना से प्रेरित है फिल्म भागवत

फिल्म भागवत सस्पेंस और जबरदस्त ड्रामा से भरपूर होगी। इसमें इस्पेक्टर विश्वास भागवत (अरशद वारसी) की कहानी है, जो एक गुमशुदा महिला की तलाश के केस की जांच करता है। लेकिन यह जांच जल्द ही धोखे, रहस्यों और संभावित तस्करी के एक अंधेरे और पेचीदा जाल में उलझ जाती है। इस सीरीज में जितेंद्र कुमार एक प्रोफेसर के रोल में दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। जी5 की हिंदी बिजनेस हेड कावेरी दास ने इसके बारे में बात करते हुए कहा, भागवत एक रोमांचक थ्रिलर है, जो भावनात्मक गहराई और सस्पेंस का शानदार मिश्रण पेश करता है। अरशद वारसी ने अपने किरदार को बहुत बारीकी और गहराई से निभाया है। वहीं, जितेंद्र कुमार एक आकर्षक और अनूठे अंदाज में दर्शकों को चकित करते हैं। सबके साथ आने से यह सिनेमाई भव्यता, साहसिक कहानी और प्रभावशाली अभिनय का संगम बन गया है। अपनी अनोखी शैली और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ, भागवत इस साल की सबसे मनोरंजक और प्रभावी फिल्मों में से एक है।

ओटीटी पर आएगी फिल्म भागवत

इस फिल्म को अक्षय शेरें डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका निर्माण जियो स्टूडियोज, बावेजा स्टूडियोज और डॉग एन बोन पिक्चर्स ने मिलकर किया है। यह फिल्म जल्द ही जी5 पर रिलीज की जाएगी। इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है।

अक्षय कुमार का आमिर खान पर तंज!

ओटीटी के आने से फिल्मों की कमाई पर असर पड़ा है, पिछले काफी वक्त से यह एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। अभिनेता आमिर खान का ऐसा मानना है कि थिएटर रिलीज के छह महीने बाद फिल्मों को ओटीटी पर आना चाहिए। उनका मानना है कि आजकल जो 2 महीने या आठ हफ्ते के बाद ही फिल्मों के ओटीटी पर आने से कमाई पर असर पड़ता है। अब अभिनेता अक्षय कुमार ने आमिर के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आमिर की बात से असहमति जताई है। साथ ही अक्षय ने आमिर के बयान पर तंज भी कसा है।

तीन महीने का अंतराल ठीक है

एबीपी लाइव के साथ बातचीत के दौरान अक्षय ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तीन महीने का फासला ठीक है। छह महीने बहुत लंबा समय है क्योंकि आखिरकार, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको डिजिटल अधिकारों के लिए भुगतान कर रहा है। उन्हें भी इस सौदे से लाभ मिलना चाहिए। इस पूरी व्यवस्था को महामारी से पहले की स्थिति में वापस जाना चाहिए, जब सिनेमाघर और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों एक साथ मौजूद थे और अच्छे से साथ-साथ चलते थे।

डिजिटल राइट्स के समय निर्माता ओटीटी प्लेटफॉर्म से पैसा ले लेते हैं

इस दौरान अक्षय ने दावा किया कि निर्माताओं, जिनमें वो भी शामिल हैं, को ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। साथ ही अपनी फिल्मों के कंटेंट को लेकर भी सचेत रहना चाहिए। इसी दौरान आमिर के बयान पर इशारों-इशारों में ताना मारते हुए अक्षय ने कहा, 'जब डिजिटल राइट्स की बिक्री की बात आती है, तो निर्माता खुशी-खुशी ओटीटी प्लेटफॉर्म से पैसा ले लेते हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं, तो हम आसानी से कह देते हैं कि हमारी फिल्मों ओटीटी की वजह से नहीं चल रही हैं। हम यह नहीं सोचते कि शायद हम सही फिल्में नहीं बना रहे हैं।' हालांकि, अक्षय ने यहां आमिर या किसी का भी नाम नहीं लिया। लेकिन यह बयान आमिर के बयान पर प्रतिक्रिया जरूर मालूम पड़ता है।

मुझे फिल्में बनाने के अलावा कुछ नहीं आता

अक्षय ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी फिल्मों के लिए प्रतिभाओं की तलाश में भी काफी ओटीटी कंटेंट देखते हैं। उनका मानना है कि ओटीटी के आने फिल्म इंडस्ट्री में सभी को फायदा हुआ है। अक्षय ने

कहा कि मेरे पास फिल्में बनाने के अलावा कोई और काम नहीं है। चूंकि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ फिल्में ही बनाता हूँ। इसलिए मुझे ओटीटी देखने के लिए काफी समय मिलता है।

ओटीटी पर जल्द फिल्मों के लाने के खिलाफ हैं आमिर

आमिर खान अक्सर ओटीटी को फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर न चलने की एक वजह मानते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि जब लोगों को फिल्मों के रिलीज के कुछ ही वक्त बाद घर बैठे फिल्म देखने को मिल जाएगी, तो वो क्यों सिनेमाघरों में जाएंगे। हालांकि, आमिर का ये भी कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नहीं हैं। हाल ही में आमिर ने अपनी फिल्म 'सितारे जमीन पर' को भी थिएटर्स के बाद किसी ओटीटी पर नहीं रिलीज किया। बल्कि उन्होंने यूट्यूब पर फिल्म को पे-पर-व्यू मॉडल के तहत लाया।

